खण्ड-06 सत्र -03 (भाग-01) / अंक-28

सोमवार 28 मार्च, 2016 / 8 चैत्र, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-03 (भाग-01) में अंक 27 से अंक 31 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 भाग (1) सोमवार, 28 मार्च, 2016/ 08 चैत्र, 1938 (शक) अंक 28

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

1.	श्री शरद कुमार	13.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
2.	श्री संजीव झा	14.	श्री सोमदत्त
3.	श्री पवन कुमार शर्मा	15.	सुश्री अलका लाम्बा
4.	श्री अजेश यादव	16.	श्री आसिम अहमद खान
5.	श्री महेन्द्र गोयल	17.	श्री विशेष रवि
6.	श्री वेद प्रकाश	18.	श्री हजारी लाल चौहान
7.	श्री सुखवीर सिंह दलाल	19.	श्री शिव चरण गोयल
8.	श्री ऋतुराज गोविन्द	20.	श्री गिरीश सोनी
9.	श्री रघुविन्दर शौकीन	21.	श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
10.	सुश्री राखी बिड़ला	22.	श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
11.	श्री जितेन्द्र सिंह तोमर	23.	श्री राजेश ऋषि
12.	श्री राजेश गुप्ता	24.	श्री महेन्द्र यादव

25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. श्री कैलाश गहलोत
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. सुश्री भावना गौड़
31. श्री सुरेन्द्र सिंह
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री मदन लाल
34. श्री सोमनाथ भारती
35. श्रीमती प्रमिला टोकस
36. श्री नरेश यादव
37. श्री करतार सिंह तंवर
38. श्री प्रकाश
39. श्री अजय दत्त
40. श्री दिनेश मोहनिया
41. श्री सौरभ भारद्वाज
42. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री अमानतुल्लाह खान
45. श्री राजू धिंगान
46. श्री मनोज कुमार
47. श्री नितिन त्यागी
48. श्री ओम प्रकाश शर्मा
49. श्री एस.के. बग्गा
50. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
52. सुश्री सरिता सिंह
53. मो. इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-3 सोमवार, 28 मार्च, 2016/चैत्र 08, 1938 (शक) अंक-28

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

शोक संवेदना

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदयस्यगण, आप सबको विदित है कि दिनांक 25 मार्च 2016 को सियाचीन गलेशियर में तैनात दो और भारतीय सैनिकों की हिमस्खलन से मौत हो गई। देश की सुरक्षा के लिये एक बार फिर सैनिकों ने अपने प्राण गंवा दिये। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की मुस्तैदी से ही भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं। सियाचीन के सैनिकों को बाहरी खतरे के अलावा कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता है। अत: उनका साहस, वीरता और सतर्कता प्रशंसनीय हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण यह अत्यधिक दु:ख का विषय है कि पाकिस्तान के लाहौर में कल शाम को एक पार्क में हुए फिदायीन हमले में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 लोग घायल हो गये। यह वास्तव में किसी स्थान विशेष पर नहीं, अपितु पूरी मानवता पर हमला है। आतंकवादियों

की कोई जाति, मजहब या वतन नहीं होता। आतंकवाद की समस्या इस समय पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। हम इस हमले की कड़ी निन्दा करते हैं तथा आशा करते हैं कि इस हमले के षडयंत्र का शीघ्र पर्दाफाश होगा और दोषी पकड़े जायेंगे।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस हमले में मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायलों के शीर्घ स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा। अपने-अपने स्थान पर सभी खड़े हों।

(सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया गया)

ओम शांति शांति, शांति।

बजट प्रस्तुतीकरण

आज हमारी एलजी गैलरी में हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री जगदीश मुखी जी आये हैं, मैं उनका हार्दिका स्वागत करता हूं। आशीष तलवार जी, कुमार विश्वास जी अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं। उन सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं।

इससे पूर्व कि माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें, वित्तीय समितियों के चुनाव संबंधी सूचना मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि कल दिनांक 29 मार्च 2016, को होने वाली सदन की बैठक के लिये नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का नोटिस आज अपराहन 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय की नोटिस ब्रांच को दिया जा सकता है। सभी माननीय

सदस्य इस ओर विशेष ध्यान दें। अब माननीय वित्त मंत्री मनीष सिसौदिया, उप मुख्यमंत्री, वित्त वर्ष 2016-17 के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं वित्त वर्ष 2016-17 का बजट इस सम्मानीय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। परन्तु इसके पूर्व मैं सदन के समक्ष उल्लेख करना चाहता हूं कि चूंकि यही बजट दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का और उनके भरोसे का, ईमानदारी से इस्तेमाल करने का, एक सदुपयोग करने का दस्तावेज है। इस बजट का मूल मंत्र है अगर नेकनियती और समझदारी से काम लिया जाये तो काम तेजी से होता है और कम लागत में होता है और जनता को भी बड़े पैमाने पर इसका फायदा मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान कई अवसरों पर इस बात का प्रमाण दिया है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रस्तावों पर आने से पूर्व मैं सदन का ध्यान बजट से जुड़ी हुई कुछ परम्परागत क्रान्तिकारी धारणाओं की ओर भी दिलाना चाहता हूं और इनमें से एक का जिक्र माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने अपने बजट भाषाण में भी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें बजट को प्लान, नान प्लान तरह के जो कन्वैनशनल सांचे हैं, उनमें से निकाल कर देखना चाहिए। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं क्योंकि प्लान, नान प्लान, यह सब जो खर्चे हैं यह आम आदमी की समझ से परे हैं, आम आदमी को तो एक बात समझ में आती है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, वही बजट है। जितना भी पैसा खर्च कर रही है, वही सरकार का बजट है। आम आदमी के लिये बजट को मेरी राय में इस रूप में समझना आसान होगा कि जो योजनाएं और प्रोजेक्ट

सरकार देश के लिये लेकर आई है, आम आदमी के लिये, उसके शुरू होने पर कितना खर्च होगा और उसके आगे चलाने पर कितना खर्च होगा। यह महत्वपूर्ण है और इसीलिये बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन में उल्लेख रखना चाहता हूं कि इस साल हमने एक बहुत स्थापित परम्परा है सभी सरकारी गलियारों में इस बात को हंसी-मजाक में लिया जाता है कि मार्च का महीना आ रहा है, बजट निपटाओ। हमने उसको रोका है, हमने लिखित आदेश जारी करके भी और एक एक डिपार्टमेन्ट को क्रिटीकल नजरिये से देखकर इस बार रोका है, वरना परम्परागत रूप से जैसे-जैसे फाईनेंशन ईयर एंड होता है वैसे-वैसे विभागों पर दबाव बनता है कि पैसा खर्च कर दो, बजट पास है, पैसा खर्च कर दो। चाहे चार कम्प्यूटर खरीद लो। चाहे पुती-पुताई दीवार को दोबारा से पुतवा दो। लेकिन पैसा खर्च कर दो, पैसा बचना नहीं चाहिए। हमने इस परम्परा को खत्म किया। हमने लिखित रूप से आदेश जारी करके और एकदम डिपार्टमेन्ट्स की स्क्रूटनी करके-करके कहा कि पैसा फिजूलखर्ची में नहीं लगना चाहिये, जनता का पैसा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ पैसा खर्च होना चाहिए। बजट से जुडी एक और धारणा अध्यक्ष महोदय, कि सरकारों की सफलता-असफलता का जो आंकलन होता है वो वित्त वर्ष में खर्च की राशि से किया जाता है। जबकि देखा यह जाना चाहिये कि जनता के पैसे का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ओपटीमम यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। जनता की कितनी उसमें भागीदारी रही, कितने प्रतिशत जनता को इसका लाभ मिला क्योंकि सरकार का मकसद सिर्फ जनता का पैसा खर्च करना नहीं है बल्कि ये भी देखना है कि उसके काम से कितने इंसानों की जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है। ये सब देखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, यहां एक और बात मैं आपसे कहना

चाहूंगा सदन के समक्ष, सदन से कहना चाहूंगा कि ये बजट हमारी सरकार द्वारा चुनाव घोषणापत्र में किए वादों को पूरा करने की एक कोशिश है, उसका एक प्रयास है। हमारे लिए चुनाव घोषणापत्र जो हमारा इलैक्शन मन्युफैस्टो है, वो हमारी सरकार और दिल्ली के नागरिकों के बीच भरोसे का एक गठबंधन है और हम अपने चुनाव घोषणापत्र को किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं मानते है। यह हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। अध्यक्ष महोदय चुनाव जीतने के बाद, चुनाव घोषणापत्र में कही गई बातों को हम जुमला कहकर खारिज नहीं करते बल्कि मैं सम्मानीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा चुनावी घोषणापत्र, हम सरकार के मंत्रीगण यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के मोबाइल डिवाइस में उपलब्ध है और हमारे लिए गीता, बाईबल, कुरान की तरह है। हम उसको देखते रहते है कि कौन सी चीज कहां खड़ी है, क्या काम हमारा कहा खड़ा है, किस वादे पर हम शुरू कर चुके है, किसको पूरा कर चुके है, किससे अभी कहां खड़े हैं और हम इन बातों को इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ये हमने दूसरों से नहीं किए, औरों से नहीं किए बल्कि ये हमने खुद से किए हैं कि हमको ये करना है जाकर, तो हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं हैं। हम अपने लिए इन वादों को याद रखते हैं कि हम यहां आए क्यों हैं? हम इस सत्ता में बैठे हैं तो किसलिए बैठे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरकार चुनाव के समय किए गए अपने वादों पर तेजी से काम कर रही है और आज दिल्ली के 90 फीसदी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घर आने बिजली के बिल आधे हो चुके हैं। दस लाख परिवारों को पानी मुफ्त में मिल रहा है और दिलचस्प बात ये है कि लोग सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर, उसमें शामिल होकर पानी की बचत भी कर रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड का रैवन्यू भी बढ़ रहे हैं।

सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति लागू करते हुए एक महत्वपूर्ण शुरूआत की है। भ्रष्टाचार के किसी कृत्य को, उसमें चाहे कितने ही उच्चे पद पर आसीन व्यक्ति शामिल हो, मंत्री शामिल हो, सरकार कार्रवाई करने में देर नहीं लगाती। ये सरकार ने साबित किया है कि सरकार ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिए व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। आज आन लाइन सर्टिफिकेट, ई-लाइसेंसिंग, आन लाइन ईडब्लूएस एडमिशन ये तमाम सुविधाएं पहली बार व्यवहारिक रूप से सामने आई हैं, लोगों को उपलब्ध हुई हैं। दिल्ली जन लोकपाल बिल विधेयक इस सदन से पारित किया जा चुका है और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी का लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने की दिल्ली सरकार की कोशिशों में केंद्र सरकार द्वारा लगातार अड़ंगा डाले जाने के बावजूद व्यवस्था की खामियों और कमजोरियों को दुरूस्त करने, राजस्व में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी करने, फिजूल खर्ची रोकने और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में हम कई जगह सफल रहे हैं। पिछले एक साल के इस तमाम अनुभव को अगर मैं दो लाईनों में समेटूं तो मैं कहना चाहूंगा कि-

'जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से,
उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से।
जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से,
उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से।'

ईमानदारी से काम करने, जनता के पैसे की चोरी और बर्बादी रोकने से जो रिसोर्सिस बच रहे हैं या एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल वैलफेयर में हो रहा

है। आज गरीब लोगों को, सबको दवाईयाँ मुफ्त मिल रही हैं, मुफ्त पानी मिल रहा है, आधे दाम पर बिजली मिल रही है, किसानों को रिकार्ड मुआवजा मिल रहा है, टाइमली मुआवजा मिल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रही है कि दिल्ली में एक ईमानदार सरकार स्थापित की जाए। ईमानदारी से सरकार चलने में कई बाधाएं हैं। दिल्ली में बिजली घोटाला हुआ, उसकी फाइल एसीबी के पास है। एसीबी पर कंट्रोल कर लिया गया है। डिस्कोम का घोटाला हुआ। पूरे एसीबी पर इसलिए कंट्रोल किया गया कि ये सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है, उसको काम न करने दिया जाए और जनता का जो पैसा बच सकता है, जनता के पैसे का सदुपयोग हो सकता है, उसको किसी तरह से रोका जाए।

अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों का विस्तार से वर्णन करने के पहले मैं सरकार की एक साहसिक 'ऑड इवन योजना' को सफल बनाने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में दिल्ली की जनता के इस प्रयोग की सराहना हो रही है। सभी जगह तारीफ हो रही है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक 'फोरच्यून मैग्जीन' ने 'ऑड इवन योजना' की इस शानदार सफलता से प्रभावित होकर दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री को दुनिया के पचास महानतम नेताओ की सूची में शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को इस बात पर भी गर्व होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है। 'ऑड इवन' में दिल्ली की जनता की पूरी भागीदारी का मैं इस सदन की ओर से अभिवादन करता हूं और 'ऑड इवन' की सफलता प्रमाण है कि जनता की भागीदारी से प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी बड़ी समस्याओं का समाधान भी

निकाला जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने के तुरंत बाद दिए गए पहले ही भाषण में जनता की भागीदारी को लेकर उन्होंने जो कहा था कि, 'आज दिल्ली का प्रत्येक नागरिक मुख्यमंत्री बना है' उनका वो वाक्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक वाक्य है और उसी के आधार पर ये 'ऑड इवन' जैसी योजनाएं जनता की भागीदारी से सफल हो पा रही है।

मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं जनता से जुड़ी हुई हैं, हमारा लक्ष्य है ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ पूरी दिल्ली का, हर तबके का विकास। दिल्ली के किसी एक हिस्से या कुछ खास लोगों के लिए दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया जाना नहीं चाहिए। हमारे लिए स्मार्ट सिटी का मतलब है दिल्ली के एक-एक व्यक्ति के लिए बेहतरीन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक से आधुनिक परिवहन व्यवस्था, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण, साफ सफाई और रोजगार के बेहतर अवसरों वाला शहर। स्मार्ट सिटी सिर्फ वही शहर हो सकता है जहां सरकार के फैसलों में ईमानदारी हो। स्मार्ट सिटी वही शहर हो सकता है जहां लोगों की भागीदारी हो और व्यवस्था हर आदमी को बराबर का सम्मान देकर चलती हों।

अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च 2016 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में वर्तमान मूल्यों के आधार पर दिल्ली का जीएसडीपी बढ़कर 5,58,745 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है जो 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपए था अर्थात् जीएसडीपी में 13% की वृद्धि हो रही है। यह अनुमान अगर वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए दिल्ली के जीएसडीपी के अनुमानों की नई श्रृंखला पर आधाारित किए गए है। स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के जीएसडीपी में 2015-16 में 8.34% बढ़ोत्तरी होने की संभावना है जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर यानि की 7.6%

से काफी अधिक है 8.34। राष्ट्रीय स्तर के जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2011-12 में 3.93% था जो 15-16 में बढ़कर 4.02% हो गया है जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43% होती है। दिल्ली के जीएसडीपी में सर्विस सैक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, जो कि 82.3% है जबकि 15.5% योगदान के साथ माध्यमिक क्षेत्र यानि औद्योगिक निर्माण वगैरह है और प्राथमिक क्षेत्र यानि एग्रीकल्चर आदि 2.2% पर है।

दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2015-16 में बढ़कर 2,80,142/- रुपए हो जाने की संभावना है जो 2014-15 में 2,52,011/- रुपए थी अर्थात् दिल्ली की प्रति व्यक्ति की आय में करीब 11% की वृद्धि हो रही है जो कि एक अच्छा संकेत है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में बढ़कर 93,231/- रुपए हो गई जो 14-15 में 86,869/- रुपए थी। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में करीब तीन गुणा ज्यादा है, यह हमारे लिए अच्छा संकेत है।

मैं थोड़ी सी बात मूल्यों की स्थिति पर भी करना चाहूंगा। हमारी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निगरानी रख रही है और बाजार के उतार-चढ़ाव के समय पर सक्रिस कारवाई करती है। उचित समय पर बाजार में हस्तक्षेप भी करती है जिसके परिणामस्वरूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि महंगाई को लेकर और बजट और दिल्ली में, दिल्ली की सरकार महंगाई को रोकने में क्या भूमिका निभा सकती है, तो मैं सदन के समक्ष डेटा रखना चाहता हूं की 2015 के दौरान दिल्ली में मुद्रास्फीती की दर सबसे कम यानि 4.9% रही है जो चैन्नई में इस दौरान 7.8 थी, मुंबई में 7.4 थी और नेशनल पर 5.7 थी, दिल्ली में ये 4.9 थी तो सरकार के हस्तक्षेप की वजह से, सरकार की निगरानी की वजह

से और यथा समय एक्टिव सक्रिय कारवाई की वजह से आज हम दिल्ली देश में सबसे निचले स्तर पर मुद्रास्फीती की दर पर खड़ी हुई है। ये दिल्लीवालों के लिए एक सुखद स्थिति है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब हम बजट पेश कर रहे होंगे तो इस डेटा को और नीचे लाकर रखेंगे।

वैश्विक आर्थिक मंदी, अब मैं वित्तीय स्थिति जो सरकार की है, दिल्ली की है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। हमने वैश्विक आर्थिक मंदी और घरेलू आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद अपनी वित्तीय स्थिति स्ट्रांग की है। हमने अपनी आय के संसाधनों में लीकेज पर नियंत्रण किया है, अपना राजस्व बढ़ाया है और अतिरिक्त संसाधन जुटाकर आर्थिक मंदी पर काबू पाया है। हम चालू वर्ष में कर राजस्व में 17% वृद्धि की उम्मीद करते है जो 2014-15 के दौरान मात्र 2.64% थी। 2.64% से 17% होना बड़ी बात है। राज्य आबकारी (एक्साईज) के मामले में हम 2015-16 में 31% की बढ़ोत्तरी की उम्मीद करते हैं जबकि 14-15 में मात्र 8.60% थी। वैट में हम इस तरह से 2.64 से 17% पहुंच गये हैं और एक्साईज में 8.60 से 31% पहुंच गये हैं इसी प्रकार स्टैंप पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत इस वर्ष 21% बढ़ोत्तरी का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष इसमें 4.3% नैगेटिव इंक्रिज था। हमारा कर जीएसटी के अनुपात में 2014-15 में 5.4% था वो 2015 में बढ़कर 5.6% हो जाने का अनुमान है। मैं यहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार कही जा चुकी एक बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि सरकारों के पास पैस की कमी नहीं होती, सरकारों के पास नीयत की कमी होती है। नीयत ठीक हो तो टैक्स कलैक्शन भी बढ़ता है, जनता टैक्स भी आगे बढ़कर देती है। इसीलिए आज हम राजस्व में 17%, एक्साइज में 21% और स्टैंप ड्यूटी में 21% की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी के साथ

बैठे हुए हैं और ये सिर्फ ईमानदारी की वजह से हुआ है, एक ईमानदार सरकार की वजह से सम्भव हो पाया है। अध्यक्ष जी बजट में चालू वर्ष का हमारा गैर योजना व्यय बाइस हजार एक सौ उन्नतीस करोड़ रुपये निर्धारित अनुमोदित किया गया था, मैं हर्ष के साथ सदन को सूचित करता हूं कि चालू वित्त वर्ष में उत्तर और पूर्वी नगर निगम को 551 करोड़ रुपये के अनेपिक्षित ऋण देने जो गैर योजना व्यय के मूल अनुमानों का हिस्सा नहीं थे, के बावजूद हम अपना कुल गैर योजना व्यय 21,565 करोड़ रुपये के स्तर तक सीमित रखने में कामयाब हुए हैं। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि सरकार ने जनता के पैसे का किफायत से इस्तेमाल किया, योजना परिव्यय जो बजट में 19 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, उसको 2015-16 के संशोधित अनुमानों में 16400 करोड़ रुपये के स्तर पर सीमित करने का प्रस्ताव है, 2015-16 में संशोधित योजना व्यय 16400 करोड़ रुपये, 2014-15 के योजना व्यय 13980 करोड़ रुपये की तुलना में 17% अधिक है, चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा समग्र संशोधित बजट 37965 करोड़ रुपये है, जबकि कुल बजट अनुमान 41129 करोड़ रुपये के थे।

अध्यक्ष महोदय, 2015-16 के लिए पूरक मांग हमारी संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 1420 करोड़ रुपये की पूरक मांग अपेक्षित होगी। अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की अपील करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2016-17 वित्त वर्ष के बजट अनुमानों पर अपनी रोशनी रखना चाहूंगा, वर्ष 2016-17 के लिए कुल बजट अनुमान 46600 करोड़ रुपये का रखा गया है, जिसमें 20600 करोड़ रुपये योजना और 26 हजार करोड़ रुपये गैर योजना व्यय के रूप में शामिल है। मैंने आपके समक्ष शुरू में

कहा था कि प्लान और नॉन प्लान ये सब जनता के बीच समझ नहीं आता है और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी केंद्र सरकार बहुत जल्द इसके बारे में निर्णय भी लेंगे और देश में एक ऐसी परिपाटी लागू करने की व्यवस्था करेंगे ताकि बजट की जो भाषाएं हैं, बजट के जो डिविजनस हैं, सांचे हैं, आम जनता भी उनको ठीक से समझ सके और मैं यहां इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं जब भी ऐसी पहल होगी दिल्ली सरकार उसमें प्रथम आगे उस पहल को स्वीकार करेगी, फिर भी अभी मैं आपके सामने जो बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, प्लान और नॉन प्लान के हिसाब से। मैंने कहा कि 46600 करोड़ रुपये का टोटल जिसमें से 20600 करोड़ रुपये योजना व्यय और 26000 करोड़ गैर योजना व्यय के रूप में शामिल है, 46600 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के लिए 36525 करोड़ रुपये राजस्व से, 996 करोड़ रुपये गैर कर राजस्व से , 381 करोड़ रुपये पूंजी प्राप्तियों से, 3117 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से, 1400 करोड़ रुपये केंद्रीय बिक्रीकर वैट के बदले जो क्षतिपूर्ति मिलती है, उससे, 1300 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित स्कीम से, 413 करोड़ रुपये सामान्य केन्द्रीय सहायता से और 325 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से, 432 करोड़ रुपये भारत सरकार के अन्य अनुदानों के जरिए जुटाए जाएंगे, यहां मैं एक बार फिर से जो कि सदन में पहले भी कह चुका हूं कि दिल्ली के लोग एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं और जब उस एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये के टैक्स में से जब दिल्ली की जनता का शेयर मिलने की बारी आती है तो उसमें 17-18 साल से 325 करोड़ रुपये मिलते रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मात्र 325 करोड़ रुपये पर

सूई अटक गई है। देश की राजधानी का विकास मात्र 325 करोड़ रुपये के शेयर के आधार पर, जो लोग एक लाख तीस हजार करोड़ रुपये के लगभग टैक्स सैंटर को दे रहे हैं, 42% शेयर बढ़ाने की सब जगह बात हुई, 32% से 42 दिल्ली को उसमें कुछ नहीं बढ़ाया। मेरी वित्त मंत्रालय के कुछ सोर्सिज से बात हुई। मुझे बताया गया कि एक हजार करोड़ रुपये इस बार करने का प्रस्ताव था लेकिन जो अडंगा डालने की राजनीति है, उसके चक्कर में उसको रोक दिया, गया और वापस 325 करोड़ रुपये कर दिया जो कि हमारी सरकार ने जो कुछ घोटाले हुए, जिसमें क्रिकेट की बात शामिल थी, उसकी वजह से उसके चक्कर में एक हजार करोड़ रुपये। फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो 46600 करोड़ रुपये हैं इनमें से 95% जो मैंने आपके सामने अभी डिविजन रखा, 95% दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार के लिए अपने रिसोर्सिज दे रही है, केवल 5% जिसमें मैंने रखा 1300 करोड़ रुपये सैंट्रल स्कीम, 413 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता, 325 करोड़ रुपये केंद्रीय कर में हिस्सेदारी और 425 करोड़ रुपये भारत सरकार से अन्य अनुदानों के रूप में, कुल मिला के 5% हमें सैंट्रल गवर्नमैन्ट से मिलेगा, 95% दिल्ली के अपने रिसोर्सिज से हम लोग ये सब करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में 46600 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय में स्थानीय निकायों के लिए एमसीडी के लिए 6919 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो कि 15-16 के बजट अनुमान में यह राशि 5908 करोड़ रुपये थी और संशोधित अनुमान में 5999 करोड़ रुपये थी यानि की एक हजार करोड़ रुपये इस बार दिल्ली नगर निगम को एक्स्ट्रा दिये जाएंगे और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि दिल्ली नगर निगम के साथी ये ध्यान रखते हुए कि ये दिल्ली की जनता

की मेहनत की कमाई का पैसा है, उसको इधर-उधर गंवाने में, फिजूल खर्ची करने में, उसमें बेईमानी करने से बाज आ के जो सफाई कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, टीचर्स की सैलरी नहीं मिलती है, सही जगह उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर सदन के समक्ष रोशनी डालना चाहता हूं वैसे तो सरकार के सारे कार्यक्रमों को अगर एक सूत्र में बांधे तो हमारी एक ही फिलॉसफी है। ये है यदि हो तो सब के लिए हो ये जिद हमारी है। बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है, हमारी सारी फिलॉसफी जिसमें हो तो सबके लिए, कुछ विशेष वर्ग के लिए, कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए स्कूल बना दो, कुछ खास लोगों के लिए कॉलेज बना दो। नहीं, बने तो सबके लिए बने, सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, मॉडल वही होना चाहिए चाहे आपके सामने रास्ता उस तरह का होना चाहिए। हमारा सारा मॉडल जो अपने कार्यक्रमों का है, इसी पर आधारित है और एक बड़ा मशहूर कोटेशन है, अमरीकी राजस्व मंत्री हैं अभी जैकब ल्यू मैं उनको पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है "The budget is not just a collection of numbers, but an expression of values and aspirations." क्या expression हैं, क्या values हैं, क्या नीड्स हैं, मैं अपने प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में उनका जिक्र करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने प्रशासन को पारदर्शी और एकाउंटेबल बनाने के लिए तरह-तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव व टैक्नीकल रिफॉर्म्स दिये हैं, पारदर्शी और समय पर सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-डिस्ट्रीक परियोजना लागू की गई हैं ताकि आम आदिम को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें, इसके तहत विभिन्न तरह की सरकारी सेवाओं जैसे की सर्टिफिकेट बनवाने, घर बैठे ऑन लाईन सर्टिफिकेट लेने, अभी तक एप्लीकेशन तो होती थी, जिसमें आप ऑन लाईन सर्टिफिकेट एप्लाई करें लेकिन आप रात को दो बजे एप्लाई करें और

कभी-भी किसी भी समय आप सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लें और आपको दफ्तर में जाना ही ना पड़े ये सुविधा पहली बार इस तरह की दिल्ली में लागू हुई है, लाइसेंस लेना, इवैंट आयोजन करने के लिए आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों आपको दिल्ली में कोई कल्चरल, फैस्टीवल या कोई और इवैंट आयोजित करनी है, उसके लिए एप्लाई करना है, आप दुनिया के किसी भी कौने में बैठकर एप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम, प्रमीशन के लिए इससे बिचोलियों की भूमिका समाप्त हो गई और जो उसमें लगे हुए लोग हैं उनकी जिन्दगी आसान हो गई, दस्तावेजों की जालसाजी रोकने में मदद मिली है और इसको आसान बनाने के लिए जो बड़े फैसले सरकार ने लिए उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि 200 तरह के एफीडेविट्स अध्यक्ष महोदय, सरकार ने समाप्त कर दिये जिनकी वजह से लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, एफिडेविट बनवाने के लिए, एफिडेविट जमा करवाने के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकार ने दिसम्बर, 2015 से सरकारी कार्यालयों में जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों के एटैस्टेशन की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है, सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को हमने इस तरह से सरल बनाया है, किसी भी स्मार्ट सरकार के लिए वाई-फाई नेटवर्क इसकी बड़ी चर्चा होती है, वाई-फाई नेटवर्क, पूछा जाता है वाई-फाई कहां गया? वाई-फाई यहां आया है, किसी भी स्मार्ट गवर्नमैन्ट के लिए वाई-फाई नेटवर्क की बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधा है, सरकार सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग मॉडल्स पर काम कर रही है, सरकार ने अब तक बसों में वाई-फाई, बुराड़ी में आउटडोर वाई-फाई और एनडीएमसी में वाई-फाई के मॉडल पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किये हैं इन मॉडलों के अनुभवों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार

दिल्ली के आम नागरिकों को उत्तम कोटि का ऐसा वाई-फाई ढांचा उपलब्ध कराएगी जिसमें सरकारी खजाने की लागत कम से कम हो। शासन प्रक्रिया में स्वराज लाने के लिए सरकार ने बजट तैयार करने में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वराज निधि पिछली बार शुरू की थी और इसको हमने 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर सफलतापूर्वक चलाया था, मोहल्ला सभाओं के जरिए जगह-जगह स्थानीय स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वहां से जो कार्यों की अनुसंशा जनता ने की, उनको अब सरकार कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 2016 में मैंने कहा कि पहले साल हमने 11 विधान सभा क्षेत्रों में किया था, 2016-17 में इस कार्यक्रम का विस्तार सभी विधान सभा क्षेत्रों में किया जा रहा है। सरकार के स्वराज विजन के अनुरूप प्रत्येक मोहल्ले को स्थानीय स्तर पर कार्यों के क्रियान्वयन के लिए धन दिया जाएगा, और मैं स्वराज योजना, स्वराज निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित करता हूं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है स्वराज की दिशा में। मैंने पिछली दफा भी कहा था। आदरणीय गांधी जी, बापू जी का फोटो यहां पर लगा हुआ है और उनका ब्रह्म वाक्य इस पर था कि स्वराज कहां है? तो जनता यहां भागीदारी निभाये। उन्होंने कहा था कि इस देश को, उन्होंने पूरे राष्ट्र के संबंध में अध्यक्ष महोदय कहा था कि इस देश को चन्द गांव, सरकार में बैठे हुए चन्द लोग नहीं चला सकते। इसे तो चार लाख गांवों द्वारा चलाया जाना चाहिए। आज हम दिल्ली के समक्ष ये ढांचा रख रहे हैं। इसको सरकार में बैठे 6 मंत्री नहीं चला सकते, बल्कि इसको तो दिल्ली की तीन हजार मुहल्ला सभाओं द्वारा चलाया जाना चाहिए और ये इसकी शुरूआत है। दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर राशन कार्ड पोर्टेबिल्टी की शुरूआत की गई है। जिसमें उपभोताओं

को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पसन्द की उचित दुकान से राशन प्राप्त करने उपभोक्ताओं का विकल्प प्रदान किया गया है। अभी तक राशन चोरी एक तरह से दादागिरी की तरह से थी। आपका राशन कार्ड है आपके पास। मैं दुकानदार हूं। आपकी मजबूरी है मेरे से लेना, लो भाई! नहीं, तो मलत लो। हमने विकल्प किया कि जिस गरीब के पास राशन कार्ड है, वो राशन लेना चाहता है और उसको मालूम है कि ये वाला दुकानदार ठीक से राश्न नहीं देता, बेईमानी करता है। पोर्टेबिल्टी है, दूसरी दुकान पर जा सकता है। उसके पास में अब ऑप्सन्श है तो इस तरह से दुकानदार जो चोरी करेगा उसके पास कोई नहीं आयेगा और जो ईमानदारी से देगा सारे के सारे इलाके के राश्न वालों को, राशन कार्डधारक उसके पास चले जायेंगे और वो जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, वो भी फोर्स होंगे ईमानदारी से काम करने के लिए। तो धीरे-धीरे अभी इसको दिल्ली छावनी क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर लिया गया है। आने वाले समय में पूरी तरह से दिल्ली में इसको लागू करने की हमारी योजना है। चालीस उचित दर दुकानों पर, एफ.पी.एस. पर प्वाईन्ट ऑफ सेल डिवाईस की स्थापना के लिए पायलट योजना शुरू की जा चुकी है। जिसमें बायोमेट्रिक पहचान के बाद राशन जारी किया जाता है। इस प्रणाली का विस्तार 6 महीने के अन्दर चौबीस सौ एफ.पी. एस. में किया जायेगा ताकि अनाज का वितरण सही ढंग से, पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी भुगतान आधार से जोड़कर वितरित किये जायेंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। जैसे ही संसद में इसकी मंजूरी मिलेगी, दिल्ली सरकार इसको सबसे पहले लागू करेगी। हमारी पूरी तैयारी है। दिल्ली में नागरिकों, विशेषकर निर्धन और उपेक्षित वर्गों जैसे रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों इत्यादि के लिए, जिनके लिए समुचित भोजन

प्राप्त करना कठिन है, उनको पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार आम आदमी कैन्टीन शुरू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखती है। क्योंकि पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की हाईजीन प्रॉब्लम थी। लोगों कहीं भी, किसी भी तरह का उपलब्ध खाना जैसा भी जिनको उपलब्ध होता है और ये मेहनतकश लोग खासतौर पर जो गली–मोहल्लों में मेहनत करते हैं, उनको किस वक्त कहां कैसा खाना मिलेगा, ये हमने नसीब पर छोड़ा हुआ है। हमारे समाज ने नसीब पर छोड़ा हुआ है। सरकार वहां दखल देके आम आदमी कैन्टीन शुरू करने का प्रस्ताव रखती है। गरीब आदमी, आम आदमी वहां भोजन कर सके, इन कैन्टीनों की कार्यप्रणाली पर, कई राज्यों में जहां हम कुछ पहले कर रहे हैं। वहां कई राज्यों से, दुनिया से अच्छा सीख रहे हैं। हां, हम उनको भी श्रेय देते हैं। कई राज्यों में इसका इस्तेमाल हुआ है और वहां सफलतापूर्वक वहां जो जनता है, उसको इसका फायदा मिल रहा है। तो इन कैन्टीनों की कार्यप्रणाली पर निगरानी और समन्वय के लिए दिल्ली सरकार में एक ब्यूरो ऑफ अफोर्डेबल मील्स की स्थापना की गयी है और आम आदमी कैन्टीन के लिए आगामी वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में ये एक तरह से हमारे गवर्नेन्स के सुधार व जनता की सरकार की ईमानदार व्यवस्था का एक खाका था, जिसमें मोटे–मोटे तौर पर ये चीजें हम कर रहे हैं लेकिन कार इश्यूज में जैसा कि हमेशा हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार के कोर इश्यूज में शिक्षा और स्वास्थ्य। पिछले एक साल में ये बात कई बार प्रूफ भी हुई है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष का बजट

पेश करते हुए भी कहा था कि जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, जो समाज शिक्षा के पहले पायदान पर ठीक से कदम रखे बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसकी समृद्धि और खुशहाली अन्त तक खोखली साबित होती है। ये मैंने पिछली बार कहा था। सरकार का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में लगने वाले धन को खर्च के रूप में नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों की खुशहाली के लिए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं जोड़ना चाहूंगा यहां पर कि हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण की नहीं, प्रबन्धन की आवश्यकता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे ढांचे बने हुए हैं। ये शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिए बने हुए हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जायेगा, वी.सीज. क्या करेंगे, स्कूल्स में अध्यापक क्या करेंगे, कैसे पढ़ायेंगे, हफ्ते भर में कैसे रिपोर्ट देंगे, ये सब बड़ा नियंत्रित ढांचा है। इसको हम रिलीज कर रहे है। टीचर्स में एनर्जी है। उसको हमने कायदे-कानूनों में, उसको हमने सरकारी आर्डर्स में कैप्चर करके, कैद करके रखा हुआ है। हम उसको एकदम रिलीज कर रहे हैं ताकि सरकारें ध्यान रखें कि जब टीचर्स लेकर आयें तो योग्य से योग्य लेकर आयें। लेकिन एक बार अपने योग्य अध्यापक ले लिया चाहे यूनिवर्सिटी में ले लिया, चाहे वी.सी. बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, विषय का अध्यापक बना दिया फिर उसकी काबलियत पर भरोसा रखिए। उसकी योग्यता का सम्मान करते हुए उसको सम्मान दीजिए। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हम जो पूरी शिक्षा में काम कर रहे हैं, हम इसी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं और हमारी सरकार शिक्षा को तीन हिस्सों में बांट के देखती है। पहला हिस्सा है शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधायें और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरा है

पर्याप्त संख्या में योग्य और एनर्जिटिक टीचर्स की टीम खड़ी करना और तीसरा है इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए इन अध्यापकों के जरिए जो योग्य अध्यापक हों, एनर्जिटिक अध्यापक हों, उनके जरिए छात्रों को ऐसा पाठ्यक्रम देना, ऐसा सिलेबस देना ताकि वो एक्सीलेन्ट प्रोफेशनल तो बने ही, जिम्मेदार नागरिक और अच्छे इन्सान बनें। थ्री फोल्ड हमारी स्ट्रेटजी, एजूकेशन को लेकर है। पिछले एक साल में इन तीनों पहलुओं पर हमने काम किया है लेकिन फिर भी हमारा एक साल का जो फोकस रहा। अगर मैं कहूं कि तीनों में से तो पहले हिस्से पर रहा यानी बेहतर सुविधायें और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर रहा और एक साल में जो काम किया, उसकी बदौलत आज दिल्ली में आज की स्थिति में 21 नये स्कूल भवन बन के पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं जो इस सेशन में शुरू हो जायेंगे और अगर इनमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि कितने-कितने शिफ्ट लग सकती हैं। कहां कितनी शिफ्ट लग सकती है। अगर 21 बिल्डिंग्स को हम दोहरी शिफ्ट में चलाना शुरू कर दें तो बयालीस स्कूल का ढांचा अगले साल से हमारे साथ जुड़ जायेगा। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में जगह-जगह, जहां-जहां बच्चों की संख्या ज्यादा थी, जहां-जहां हमारे पास स्पेस उपलब्ध था, आठ हजार नये कमरे तैयार हो रहे हैं और सम्भवत: जुलाई के महीने से हम इन क्लास रूमस का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आठ हजार क्लास रूमस को अगर मोटे तौर पर देखें तो तीस-चालीस कमरे स्कूल में होते हैं, पचास तक भी ये सब लैब्स लगाके मान लें तो दो सौ स्कूल के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर हम जुलाई के महीने से और जोड़ देंगे इन 21 स्कूल्स के अलावा और ये अधिकतर रूम्स जो बन रहे हैं, ऐसी जगह बन रहे हैं जहां डबल शिफ्ट चल रही हैं। जहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष

महोदय, तो इस तरह से टोटलीटी में देखें कमरों की उपलब्धता, आठ हजार कमरों की उपलब्धता बढ़ते ही दो सौ स्कूल के बराबर यानी दो शिफ्ट में देखेंगे तो चार सौ स्कूल के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारा इससे और 21 बिल्डिंग नयी यानी 42। पहले ही साल में चार सौ बयालीस नये स्कूलों के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर हम लोग एजुकेशन के सिस्टम में जोड़ रहे हैं और ये बड़ा योगदान है और ये इसलिए हो पा रहा है कि पिछले साल सदन की अनुमति से सदन के समक्ष हमने शिक्षा का बजट दोगुना किया और जिसको हम सबने यहां सहर्ष स्वीकार किया। अगले वित्त वर्ष में शिक्षा सम्बन्धी बजट प्रस्तावों पर आने से पहले सदन के समक्ष मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज पिछले एक साल से काम करते हुए दिल्ली की हर एक सरकारी स्कूल में आपको साफ-सफाई अच्छी मिलेगी। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गयी है। सारे टॉयलेट ठीक करा दिये गये हैं। बेटियों के लिए अलग से टायलेट उपलब्ध करा दिये गये हैं। सभी स्कूलों में पीने के पानी के इन्तजाम हो चुके हैं और सभी क्लासेज में नये ग्रीन बोर्ड लगा दिये गये हैं। वैसे प्रचलित भाषा में उनको ब्लैक-बोर्ड कहते हैं लेकिन आजकल ब्लैक-बोर्ड की जगह ग्रीन-बोर्ड पर लिखने के चलन हैं तो सभी क्लास रूम्स में जहां दिखता भी नहीं था कि क्या चॉक से लिख रहे हैं। पेन्टिंग है कि डेन्टिंग है, समझ में नहीं आता था। सभी क्लास रूम्स में जा-जाके बोर्ड लगा दिये गये हैं और अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद स्कूल्स में जा-जाके करीब पिछले एक साल में जब से हम सरकार में आये हैं। हमने, मैंने खुद करीब सौ सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है और मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। एक और बड़ा कदम हमने उठाया है कि अध्यापक और प्रधानाचार्य इनके जिम्मे पढ़ाने का काम रहे।

अब एक व्यक्ति जिसको मैं चाहता हूं डेढ़ हजार बच्चों की एजूकेशन का ध्यान रखे, अचानक उसका पूरा फोकस इस पर रहता है कि टायलेट में पाईप फटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, जल बोर्ड वाले सुन नहीं रहे, प्रिसिंपल का काम यह देखना है जो डेढ़ हजार बच्चे और 50-100 टीचर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका समन्वय ठीक रहे, पढ़ाई का समन्वय ठीक रहे। इसीलिए सरकार ने पहली बार निर्णय लिया है कि अध्यापकों को, और अध्यापकों को हम लगाए रहते हैं जनगणना में और फैमिली रजिस्टर भरने में, पहली बार हमने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए आर्डर किये कि कोई टीचर जनगणना या फैमिली रजिस्टर के काम में नहीं भेजा जाएगा। मुश्किल कदम था अगर प्रशासन के प्वाईंट ऑफ व्यू से देखें, उप-मुख्य मंत्री होने के नाते देखें तो यह एक मुश्किल कदम था क्योंकि अल्टिमेटली फेमिली रजिस्टर भरवाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, मुख्य मंत्री जी के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद यह कड़ा निर्णय लिया कि कम से कम अध्यापकों को इस काम में न भेजा जाएगा, अध्यापकों का जो टैलेंण्ट, है, बच्चे खुश होंगे इस बात से उनके टीचर्स बहुत गायब रहते थे मतगणना के काम से। आज सदन में उपस्थित है बच्चे भी बात को सुनने के लिए। दूसरा काम हमने इसमें किया है कि स्कूल बिल्डिंग और जो सुख सुविधाएं है जो प्रिन्सिपल के जिम्मे देखने का काम है देश में पहली बार आज तक किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं है। हमने स्कूल्स में एस्टेट मैनेजर नियुक्त किये हैं, हरेक स्कूल की बिल्डिंग का एक एस्टेट मैनेजर है। ये एस्टेट मैनेजर रोजाना अपने-अपने स्कूल में साफ-सफाई, पानी, टायलेट की स्थिति ये सारी सूचनाएं सुबह स्कूल खुलने से पहले या दोपहर का स्कूल खुलने से आधा घंटे पहले वहां पहुंचकर वहां की पूरी विडिया क्लिप बनाकर हमें जमा

करेंगे और एक से दो घंटे के अन्दर अपने सुपीरियर ऑफीसर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह को और एक मोबाईल एप बना रहे हैं उनके लिए। उसके जरिए हमें उपलब्ध कराएंगे और अगले एक घंटे के अंदर डिप्टी डायरेक्टर वगैरह जो ऑफिसर्स है, उन्होंने क्या-क्या एक्शन लिया, उन कम्पलेंट पर और उसमें अगर कोई कमी है तो उसमें जो भी एक्शन लिया, उसकी तमाम जानकारी ले करके यानि स्कूल खुलने के दो से तीन घंटे के अंदर-अंदर शिक्षा निदेशालय और शिक्षा मंत्री के पास में एक-एक स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ये रोजाना होगा तो इस तरह से जो एक साफ सफाई और टॉयलेट्स और बेसिक फेसिलिटी का मामला है, हमें पूरी उम्मीद है कि यह व्यवस्था धीरे-धीरे लागू हो रही है। अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से स्मूथली लागू हो जाएगी। स्थिति बहुत ठीक हो जाएगी।

इस तरह एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत सरकार इस साल आने वाले वर्ष में हर एक स्कूल के हर एक क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। इन सीसीटीवी कैमरों की फीड इन्टरनेट के जरिए अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को, अभिभावकों को उपलब्ध रहेगी। पेरेण्टस भी देख सकेंगे कि उनका बच्चा जिस क्लासरूम में पढ़ रहा है वहां हो क्या रहा है। घर पर बैठकर अपने मोबाइल से देख सकेंगे। मैं इस योजना के लिए जो सीसीटीवी लगाने की योजना है वर्ष 2016-17 में 100 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों के पीछे हमारा मकसद यही है कि तीन साल के अन्दर-अन्दर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राईवेट स्कूल से बेहतर

स्थिति में ला दें। इसके लिए हमने योग्य शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की है। साढ़े पांच हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया एग्जाम वगैरह के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गेस्ट टीचर्स को स्थाई होने के विशेष अवसर दिये जाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, फाईल एलजी साहब के साथ discussion में है और इसके लिए 9623 अध्यापकों की नई पोस्ट सृजित कर ली गई है। अध्यक्ष महोदय पिछले वर्ष में जहां सुविधाओं और infrastructure पर फोकस रहा, अगले साल हम अध्यापकों को प्रधानाचार्यों की विशेष ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे यह भी जरूरी है। हमने अपने अध्यापकों को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन training institutes में भेजने की योजना बनाई है, इनमें हावर्ड, कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय के एजुकेशन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है। एस.सी.ई.आर.टी. के ट्रेनिंग क्योंकि आज जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लास रूम्स में उन्होंने जिस वक्त एमएससी या बीएड या सीटेट किया, उसके बाद में उनके सबजैक्ट को लेकर कुछ-कुछ ट्रेनिंग तो हुई लेकिन जो समाज है, वह तेजी से बदल रहा है। जिस वक्त उन्होंने एमएससी या एमए या पीएचडी किया उस वक्त बच्चे उनके हाथ में या उनकी जनरेशन के हाथ में गूगल और मोबाईल तो होता ही नहीं था, टीवी उस स्पीड से नहीं होता था आज समाज और परिवार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उस बदलते सामाजिक परिवेश के हिसाब से टीचर्स अपने ऐटीट्यूड को अप-डेट रख सके, अपने आप को अपडेट रख सकें, प्रिन्सीपल्स को पता हो जिन बच्चों को डील कर रहे हैं वो 20 साल पुराने वाले बच्चे नहीं है। आज जो बच्चा आपके पास में पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके पास में आपसे ज्यादा इन्फोरमेशन मोबाइल में और

परिवार में उपलब्ध है, टीवी में उपलब्ध है। इन सारी चीजों को देखते हुए, हम टीचर्स को एडवांस ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों के द्वारा और एससीईआरटी की जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उसके कार्यक्रमों को भी हमने अप-डेट किया है। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में हमने 102 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है अध्यक्ष महोदय कि 2015-16 में जो टीचर्स ट्रेनिंग का प्रावधान था, वो 9.4 करोड़ रुपये का था इस बार हमने 102 करोड़ रुपये यानि की ग्यारह गुना कर दिया है। शिक्षकों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम 11 गुना एक्सपैण्डीचर दूसरे स्कूलों में एक ओर नई चीज जो हम शुरू कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करके उन्हें संगीत, नाटक, कला क्योंकि (मल्टी डॉयमेन्शनल ग्रोथ) होनी चाहिए बच्चें की, इसके लिए प्रशिक्षण देने के लिए अलग से पहली 8 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, इसमें स्कूल के मैदानों की छुट्टी के बाद खेल संगठनों के लिए खोलना, मैदानों को 55 स्कूलों में फुटबाल, टेनिस के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड तैयार कराए जा रहे हैं, सरकार दिल्ली में खेल प्रतिभा विद्यालय शुरू करने और एक स्पोर्टस युनिवर्सिटी शुरू करने पर भी काम कर रही है। खिलाडियों को प्रोत्साहन देने और स्पोटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को अप-ग्रेड करने के लिए इस साल हमने 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने 205 स्कूलों में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क के तहत 9वीं से 12वीं कक्षाओं की कक्षाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है। हमारा मकसद है कि बच्चे जब स्कूल से निकले तो उसके अंदर बेहतरीन रिसर्चर, प्रोफेशनल या एकेडेमिक्स में आगे

बढ़ने की योग्यता तो हो ही, साथ में तुरंत कुछ कर सकने का हुनर भी हो। आदरणीय कलाम साहब हमारे दिल्ली सचिवालय में आए थे। वो एक तरह से पूरे देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक गाइडेंस के एक रूप में उनकी सोच को लिया जाता है। उनसे हमें गाईडेंस मिली थी, मैं उनके घर पर भी उनसे मिलने गया था अधिकारियों के साथ में और उनको निमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा ख्वाब है कि बच्चे जब स्कूल से निकले तो उनके पास दो सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक एकेडेमिक्स के लिए और एक उनके जीवन स्किल्स के लिए, लाइफ स्किल्स अर्निंग स्किल्स के लिए उसके लिए हम यहां 9^{th}, 10^{th}, 11^{th}, 12^{th}, में पूरा फोकस कर रहे हैं और इसके लिए हमने 152 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया है। मैं सदन की सूचना के लिए बता दूं कि यह भी प्रावधान इसमें भी बहुत उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले यह प्रावधान 12 करोड़ रुपये का था, उसको बढ़ाकर 152 करोड़ इस बार कर रहे हैं और इस तरह से कलाम साहब के सपने को सच करने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे इस साल। पहले ही वर्ष में हमने, 205 स्कलों में वोकेशनल कोर्सेज में करीब 45 हजार छात्रों ने दाखिला लिया वोकेशनल कोर्सेज में छात्रों की इतनी दिलचस्पी को देखते हुए सरकार ने पूरी दिल्ली में इस साल 100 से ज्यादा स्मार्ट केरिअर कॉलेज शुरू करने का भी निर्णय लिया है। ये स्मार्ट करीअर कॉलेज अब अलग-अलग क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले निजी कंपनियों को संस्था द्वारा चलाए जाएंगे। स्मार्ट करीअर कॉलेज में छात्रों अलग-अलग क्षेत्रों में स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले वित्त वर्ष में स्मार्ट करीअर कॉलेज के जरिए कम से कम 50 हजार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि का अलग से

प्रावधान किया गया है। सरकर ने दिल्ली में युवाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग देने के लिए स्टेट एप्रन्टिसशिप स्कीम को भी दुबारा शुरू किया है जो 2006 में बंद कर गई थी। सरकर ने नंद नगरी और मंगोल पुरी में दो नई आईटीआई इस साल शुरू कर दी है। रणहोला, बक्करवाला, जोनापुर में नई आईटीआई और वर्ल्डक्लास स्किल सैंटर का काम तेजी से चल रहा है। आईटीआई कोर्सेज को वाइब्रेण्ट बनाने के लिए हमने गणित, साइमेन्स, माइक्रोसॉफ्ट लेबरनट नताशा जैसी कम्पनियों के साथ कान्ट्रेक्ट किये है ताकि उनकी जो ऑन गोइंग एक्सपर्टस हैं वो हमारे आईटीआईज में आ सकें और हमारी आईटीआई में पढ़ने वाले बच्चे मार्डन टैक्नालॉजी के साथ में एकजुट होकर कंपनियों में जा सकें। राजोकरी में इस साल सरकार नया पॉलीटैक्नीक शुरू कर रही है। मंडोली, कादीपुर, बक्करवाला और झड़ोदा माजरा में पॉलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट बनाने का काम हम तेजी से कर रहे हैं। स्मार्ट करीअर कॉलेज, आईटीआई और पोलिटैक्निक में कोर्सेज करने वाले छात्र ग्रेज्युएशन या उससे आगे की पढ़ाई कर सके इसके लिए सरकार ने बेचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज प्रोग्राम पिछले साल शुरू कर दिये हैं तो आईटीआई और पोलीटैक्नीक करने वाले छात्र अगर फर्दर लर्निंग के लिए जाना चाहें तो डिग्री कोर्सेज में भी जा सकते हैं, तो ये पढ़ाई काउंट होगी वहां पर। स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए रोहिणी और धीरपुर में अम्बेडकर युनिवर्सिटी के नए परिसरों का निर्माण चल रहा है, इसके अतिरिक्त अगले सत्र से अम्बेडकर युनिवर्सिटी का एक नया परिसर कर्मपुरा में शुरू होगा। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनिस स्टडीज आगामी वर्ष में अपने-अपने नए भवनों में चले जाएंगे। आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज, भागिनी निवेदिता कॉलेज और जीजीएस आईपीयू के पूर्वी कैम्पस

का निर्माण 2016-17 में शुरू किया जाएगा। आगे चल कर विवेक विहार, मंडोली और नरेला में नए कॉलेजों के निर्माण की योजना है। सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन कॉलेजों में 2nd, शिफ्ट सांध्य कालीन कक्षाओं और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 7 कॉलेजो में नए पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे जो बच्चे अभी 12वीं, पास करके जाते हैं, उनको हमें पूरी उम्मीद है कि जो कट-आफ है, वो कुछ नीचे लाने में मदद मिलेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि लम्बे समय से प्रतिक्षित दिल्ली फार्मास्युटिकल साईंस एंड रिसर्च युनिवर्सिटी इसने 2015-16 से काम करना शुरू कर दिया है। हमने नेता जी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित कर दिया है और वो भारत सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित है। खेल विश्वविद्यालय और कौशल विकास विद्यालय के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और 2016-17 में इन पर काम शुरू हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के दूसरे चरण का निर्माण पूरे जोरों पर है और इसके पूरे होने पर इस संस्थान में भी सीटों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हमारे विद्यार्थियों के टैक्नोलोजी रेनोवेशन से जुड़े हुए विचारों को विकसित होने का वातावरण मिल सके, इसके लिए हमने शैक्षिक संस्थानों के लिए इन्क्युवेशन सैन्टर शुरू किए हैं। छः अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में हमने इस बार फाइनेंशियल कन्ट्रीब्यूशन दिया और हमारी अगले साल भी अन्य संस्थानों में भी इन्क्युबेशन सेन्टर शुरू करने के लिए अलग-अलग एजुकेशन इंस्ट्टीट्यूट को अनुसंधान, उद्यमशीलता को रेनोवेशन का सेंटर बनाने के लिए योजना है।

अध्यक्ष महोदय मैं शिक्षा के क्षेत्र में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कुल 10690 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें से 4 हजार 645

करोड़ रुपये योजना के लिए और कुल योजना परिव्यय का जो 23% है, इसके लिए है और योजना के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय शिक्षा के क्षेत्र में है।

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि बजट के जो प्रस्ताव थे वो तो परसों तक हमने पूरे तैयार कर लिए अब बजट 4-5 दिन 10 दिन से लगातार काम ज्यादा चल रहा था। फिर आदत पड़ गई अब तो कुछ ज्यादा काम करना चाहिए तो कल का काम थोड़ा छुट्टी का था। अध्यक्ष महोदय, तो वित्त मंत्री के रूप में मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैंने देखा कि देश में बाकी राज्यो में क्या स्थिति है। सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट में क्या स्थिति है तो सैन्टर गवर्नमैन्ट में हर साल एजुकेशन का बजट लगातार घटाया जा रहा है। हर साल लगातारा घटाया जा रहा है। मेरे पास में डेटा है। 2012-13 में 4.7% था, एजूकेशन पर बजट, 2013-14 में घटाकर और ये निरन्तर चल रहा है, irrespective of political leadership 2013-14 में 4.6% सरकार बदल दी। लोगों ने कहा कि यह तो ठीक नहीं हो रहा। 2014-15 में 4.1%, 2015-16 में 3.8% और इस बार 2016-17 के लिए जो दिये हुआ है उसमें 3.7%। यानि हर साल शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है केन्द्र के स्तर पर और मेरे पास में पूरे देश के डेटा है अध्यक्ष महोदय। ये सभी राज्य के, केन्द्र शासित राज्यों का डेटा है सदन के समक्ष मैं आपको कापी भी उपलब्ध करा दूंगा। किसी भी राज्य में शिक्षा में पिछले 15 साल का 2000 से लेकर और 2015 तक 2015-16 तक कहीं भी एवरेज लगभग-लगभग 10% 11%, 13% तक का एजूकेशन पर खर्च हुआ है। 20% तक कभी कभार कोई राज्य गया है लेकिन उससे ऊपर तो कोई नहीं जा रहा। ये देश की शिक्षा के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। हमने पिछले साल भी और इस साल भी सबसे अधिक हिस्सा बजट का दिल्ली

के लोगों की कमाई का शिक्षा पर खर्च करने की योजना बनाई है और इस साल भी करेंगें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकार के दूसरे फोकस एरिया हैल्थ पर आता हूं। हर साल दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों से करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं ओपीडी में आते हैं और 6 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए इतनी बड़ी आवश्यकता को पूरा करना एक कठिन काम है और इसके लिए पब्लिक हैल्थ सैक्टर में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है और बेहतर मेनेजमेंट सिस्टम की भी तो दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से हैं। इसके लिए पिछले साल भी स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर हमारी सरकार ने डेढ़ गुना किया था। आगामी वित्त वर्ष में भी पब्लिक हैल्थ सैक्टर सरकार के विकास कार्यों में केन्द्र पर रहेगा और मैं जानबूझ कर यह शब्द यूज कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। पब्लिक हैल्थ सैक्टर पर खर्च करना भी विकास है, डवलपमेंट है, क्योंकि डवलपमेंट की पता नहीं किस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब तक पुल नए नहीं बनेंगे तब तक डवलपमेंट, अब मैं उस पर भी आऊंगा लेकिन पता नहीं कहां लिखा हुआ है, सडकें और पुल नहीं बने तो डवलपमेंट किया ही नहीं। मेरे से कई बार पूछा लोगों ने साहब वो तो ठीक है, स्कूल बना लिए डवलपमेंट पर कितना पैसा खर्च किया। अरे स्कूल बन रहे है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इससे अगर डवलपमेंट नहीं होगा तो फिर डवलपमेंट होता किस से है? मुझे इकोनोमिक्स कहां से पढ़ानी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी मुझे बता दें? मैंने इसीलिए जानबूझ कर शब्द यूज किया है। आगामी वित्त वर्ष में भी पब्लिक हैल्थ सैक्टर सरकार के विकास कार्यो में केन्द्र पर रहेगा और सरकार इस को डेवलपमेंट मानती है। ऐतिहासिक फैसला लेते हुए

दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी, 2016 से दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी दवाईयों और डायग्नोस्टिक टेस्टस मुफ्त कर दिये हैं। सरकार दिल्ली के पब्लिक हैल्थ सैक्टर को मजबूत करने के लिए जैसे मैंने एजुकेशन में कहा, मैंने कहा कि ये सिर्फ बजट आंकड़ों का नहीं है। सरकार का पूरा व्यू प्वाइंट है जैसे एजुकेशन में मैंने कहा कि थ्री स्पेयर परिधियों में मैं देखता हूं उसी तरह से होस्पिटल्स का काम, स्वास्थ्य के काम को भी हमने थ्री स्टेज थ्री टियर सिस्टम बनाया है। सरकार हैल्थ में तीन स्तरीय प्रणाली की योजना पर काम कर रही है और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में पब्लिक हैल्थ सैक्टर को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य में ये अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा में उसके डेटा भी रखूंगा। अभी तक जो सरकारें काम करती थीं, प्राईवेट हॉस्पिटल्स, प्राईवेट स्कूल्स को आगे बढ़ाने पर काम करती थी और प्राईवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाने का एक जाहिर सी वजह है कि भैया हॉस्पिटल को प्रमिशन देने में भी कमिशन है और उसके बाद मालिक भी वही लोग है जिनको पोलिसीज बनानी थी और हॉस्पिटल के नाम पर किसी को लूट लो। मरता हुआ आदमी अगर आए और कहे बचा लो। तो कहीं जमीन बीवी के गहने, कहीं से उधार लेने की क्षमता है? आदमी कहता है ले लो जी लेकिन बचा लो। ये ऐसा सेन्सिटिव इश्यू है इसीलिए सब कुछ कि प्राईवेट हॉस्पिटल्स बना दो, सब खुश है प्राईवेट हॉस्पिटल बनाने में, नेताओं के प्राईवेट हॉस्पिटल बने हुए हैं, अफसरों के बने हुए हैं, जितने समाज में प्रभावशाली लोग है, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, हैल्थ एजूकेशन, कोई फिल्मों से पैसा कमा कर आ जाता है वो भी कहता है कि मैं भी हैल्थ, कोई हलवाई की दुकान से निकाल लाता है वो भी कहता है कि मैं भी हैल्थ में लगाऊंगा जी, एजूकेशन

में लगाऊंगा। एबीसीडी नहीं पता मैडिकल का पर क्यूं लगाते हैं, क्योंकि उसको सीधे-सीधे ह्यूज प्राफिट है अध्यक्ष महोदय और इससे जनता का बहुत नुकसान है, समाज का बहुत नुकसान है इससे। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश में पब्लिक सरकारी हैल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए किसी भी राज्य में ये सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होगा। मैं उसका खाका आपके सामने रख रहा हूं। सरकार की इस थ्री टियर योजना में सबसे पहले पायदान पर मोहल्ला क्लीनिक। स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिक जरूरतें है मौहल्ला क्लीनिक के माध्यम से लोगों की दहलीज पर मुहैया कराएंगे, करा रहे हैं। मौहल्ला क्लीनिक का डिजाईन आम नागरिकों की सामान्य स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रख कर किया गया है। इन क्लिनिक्स में व्यापक डायग्नोस्टिक टेस्टस तो किये जाऐंगे और सभी जरूरी दवाईयां भी दी जाएंगी लेकिन इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा। मैंने कहा थ्री टियर है पहले टियर में दवाई मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, एक दम घर के बाजू में होगी, स्पेशलिस्ट नहीं होगा। ये हमारा पहला और ये केवल सिंगल डॉक्टर ओपीडी क्लीनिक होंगे। दूसरा उसमें जो मौहल्ला क्लिनिक हैं, काफी सफलता पूर्वक हमने पहला मौहल्ला क्लीनिक बनया था। वो काम कर रहा है, और कुछ महीने के अंदर दुनिया भर में जो लोग पब्लिक हैल्थ सैक्टर पर नजर रखते हैं सरकारी हैल्थ सिस्टम पर नजर रखते हैं, उन्होंने इनकी जमकर तारीफ की है। वाशिंटन पोस्ट और शिकागों ट्रिब्यून जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अखबारों में दिल्ली के मौहल्ला क्लीनिक मॉडल का अध्ययन करने के बाद टिप्पणी की गई है बहुत बड़ी टिप्पणी है। अध्यक्ष महोदय इस सदन के लिए बड़े गर्व का विषय है कि वाशिंटन पोस्ट और शिकागों ट्रिब्यून जैसे अखबारों में टिप्पणी छपी है कि अमेरिका जैसे देशों को भी अपने पब्लिक

हैल्थ सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए दिल्ली के मौहल्ला क्लीनिक से सबक लेना चाहिए। बहुत सीखते थे इन लोगों से, विकास का पश्चिमी मॉडल। आईए अब हम आपको स्वास्थ्य का भारतीय मॉडल सिखाते हैं और ये हम नहीं कह रहे उनके अपने अखबार कह रहे है उनके अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप हम से सीख लो ये दिल्ली से सीख रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। सरकार ने पूरी दिल्ली में इस साल के अंत तक 1000 मौहल्ला क्लिनिक्स की स्थापना के लिए टैंडर प्रोसेस शुरू कर दिये हैं, टैंडर हो चुके हैं। लेकिन इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए तुरन्त किराए पर जगह लेकर 100 नए मौहल्ला क्लीनिक्स तुरन्त खोल दिये जाएंगे। तो ये पहला टीयर है हमारा दिल्ली में पब्लिक हैल्थ सिस्टम का। दूसरा टीयर है पोली-क्लीनिक। मैंने कहा कि पहले क्लीनिक में जो पहला टीयर है उसमें स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। पोली-क्लीनिक में मौहल्ला क्लीनिक से एक कदम आगे बढ़कर विशेषज्ञ और टैस्ट की सुविधा होगी लेकिन इसमें अस्पतालों की तरह मरीजों को भर्ती करने की सुविध नहीं होगी। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा। पोली-क्लीनिक की ओपीडी में मैडिकल स्पेशल्स्टि, स्त्री रोग, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ हर रोज उपलब्ध होंगे ताकि कुछ और जैसे हड्डियों के विशेषज्ञ, नेत्र, ईएनटी विशेषज्ञ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग दिन में, चुने हुए दिनों में आएंगे। ये पोलिक्लीनिक सरकार के लैब नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े होंगे और इन क्लिनिक्स में प्रॉपर डॉयग्नोस्टिक टेस्टस सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे परीक्षणों की सुविधा भी क्लिनिक्स में उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है और सरकार पूरी दिल्ली में 150 पोली-क्लिनिक्स खोलने की योजना पर काम कर रही है जिसमें से 22 अब तक चालू किये जा चुके हैं। तो ये हमारा

पब्लिक हैल्थ सिस्टम का सेकेण्ड टियर है। ये आम आदमी को सहजता से उपलब्ध है। दिल्ली की पब्लिक हैल्थ सिस्टम पब्लिक, हैल्थ केयर सेक्टर का तीसरा टियर हॉस्पिटल है। आज खांसी बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के लिए भी लागों को लम्बी-लम्बी लाईनों में हॉस्पिटल में जाकर लगना पड़ता है और उसका नुकसान दो स्तर पर होता है। एक तो वहां पर बैठे हुए स्पेशलिस्ट को वहां के पूरे जो हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम है, वो लंबी-लंबी लाइनें, छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लगने वाली ओपोडीज की लंबी लाइनें जिनको हम मौहल्ला क्लीनिक या पोलीक्लीनिक पर निपटा सकते हैं। उनकी वजह से वहां हॉस्पिटल में मेस-अप हो जा रहा है स्पेशलाइज करेगा ये सिस्टम इसलिए पैरालाइज्ड हो जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल्स के डाक्टर्स है, उनकी भी विशेषज्ञ सुविधाएं भी सामान्य बीमारियों के इलाज में ठप्प हो जाती है। सरकार की योजना है कि अस्पताल के बोझ को कम करके मौहल्ला क्लीनिक और पोलीक्लीनिक को इस काम में सक्षम बनाया जाए इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और रोगियों के अनुकूल माहौल बनेगा इस व्यवस्था से डॉक्टर्स, नर्सिज, पैरामेडिकल स्टाफ की जो ऐफिसिएसेंसी है, वो भी बढ़ेगी। मौजूदा हॉस्पिटल्स को रिमॉडल कर रहे हैं और कई नए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। इन सुधारों से राजकीय अस्पतालों में अगले दो साल में 10 हजार एडिशनल बेड्स की उपलब्धता हो जाएगी। सरकार ने व्यापक हैल्थ इन्फॉरमेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम की रूपरेखा तैयार कर ली है जिसमें एक यूनिक आईडी के साथ नागरिकों को हैल्थ कार्ड प्रदान करना शामिल है। इसमें रोगी से संबंधित जानकारी का रिकार्ड ऑनलाईन रखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है और इसको आगे बढ़कर हम स्कूल सिस्टम से भी जोड़ेंगे। एक-एक बच्चे का बचपन से रिकार्ड चलता

रहे लेकिन अभी पहले हैल्थ सिस्टम में लागू कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो और किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचे तो आज अध्यक्ष महोदय, उसको आप पूछिए और मैं समझता हूं कि आपके साथ भी ये होगा कि अगर आपको कोई बीमार हो और आप किसी डाक्टर को दिखाने जाएं और आपसे डॉक्टर पूछ ले कि पिछली बार जब दिखाया था तो डॉक्टर का नाम क्या था। आपको हॉस्पिटल याद होगा डॉक्टर का नाम याद हाने की संभानाएं कम है। चलो डॉक्टर का नाम भी याद हो सकता है क्या दवाइयां दी थी, क्या टेस्ट किए थे, उन टेस्ट्स में क्या निकला था, तो बिल्कुल याद नहीं रहता और अगर याद रहा तो फिर ज्यादा बीमार हो जाता है आदमी को इसलिए सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध होगा। आप किसी भी दुर्घटनावश, बीमारीवश कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं किसी भी डॉक्टर के पास जाएं सारा डेटा आपको कब, कहां, क्या बीमारी हुई किस डॉक्टर ने क्या टेस्ट लिया वो सारी चीजें और क्या दवाई दी गई, पूरी हिस्ट्री वहां पर आपके बारे में उपलब्ध होगी और इस तरह का पूरा एक इंटीग्रेटिड सिस्टम हम लोग उस पर तैयार करने पर काम कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसिज स्वास्थ्य प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकार पीपीपी के अन्तर्गत लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विजिस को अपने क्षमताओं का विस्तार करेगी। इसके तहत स्थापित की जाने वाली लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए 70 करोड़ रुपये टेलिरेडियोलॉजी के लिए 10 करोड़ रुपये और सीटी, एमआरआई सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सरकार दवाओं और उपकरण आदि की खरीद और अन्य लॉजिस्टिक जुटाने के लिए सप्लाई चैन मैनेजमेंट में व्यापक सुधार कर रही है और इसके लिए एक स्वास्थ्य निगम की स्थापना की जा रही है।

दवाओं, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए 410 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि आज दिल्ली के सभी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलने लगी है और इसकी चर्चा चारों तरफ है कि दवाइयों के लिए इसमें खूब बेईमानी भी होती थी और मरीजों को भी परेशानी होती थी। आज पूरे देश में ऐसा नहीं है कि दवाइयां आपको मिलने की गारंटी है फ्री में मिलने की गारंटी है और टेस्ट फ्री में होने की गारंटी है। कैट एंबुलेंस के वर्तमान बेड़े को विस्तार करने के लिए इसमें 100 सामान्य और 10 अल्ट्रा मार्डन एंबुलेंस जोड़ने का प्रस्ताव है। एंबुलेंस की डिलीवरी जून, 2016 तक हो जाने की संभावना है। राज्य में 5 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं जिसमे दुष्कर्म पीड़िताओं को तत्काल चिकित्सा और पुलिस परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है ऐसे दो और केन्द्र जल्दी ही राव तुलाराम हॉस्पिटल और बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में काम करने लगेंगे। मैं 2016-17 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5259 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 3200 करोड़ रुपये का योजना बजट शामिल है जो कुल योजना व्यय का 16% है।

अध्यक्ष महोदय, फिर से मैं एक डेटा दिखाना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। मैंने कल फिर ये भी रिसर्च किया कि बाकी राज्य हॉस्पिटल पर और हैल्थ पर कितना और पब्लिक हैल्थ पर कितना खर्च कर रहे हैं। जो मैंने बात कही कि सब प्राइवेट में इन्वेस्ट करवा-करवाकर के खुश है क्योंकि वहां कमीशन से लेकर के सबमिशन तक सब मिलता रहता है। ये डेटा बता रहा है कि किसी भी राज्य में 2000-01 से डेटा है और पिछले साल तक डेटा है। किसी भी राज्य में कभी भी इन 15 सालों के दौरान कभी भी पब्लिक हैल्थ सैक्टर का एक्सपेंडिचर डबल डिजिट तक परसेंटेज में नहीं गया यानि कि 10% तक किसी

ने भी नहीं किया आज तक 15 साल का डेटा कह रहा है। हमने पिछले साल भी किया और इस साल फिर से हम कह रहे हैं 16% खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऑड-ईवन योजना का जिक्र मैंने किया और मैं सार्वजनिक परिवहन की कुछ मुद्दों पर आता हूं। सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़, घंटों का ट्रेफिक जाम, ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी ये सारी समस्यायें हम दिल्ली वालों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुरक्षित, सुगम एकीकृत और मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदान करने के लिए कमेटिड है। हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए और वाहनों की भीड़ में कमी लाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मौजूदा संसाधनों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डीटीसी के बेड़े में इस वक्त 4461 बसें है जिनमें 3781 लॉ फ्लोर और 680 स्टैण्डर्ड फ्लोर बसें है। सरकार 2016-17 के दौरान 1000 नई स्टैण्डर्ड साइज यूएसबी-II कंपलाइन लॉ फ्लोर हाइट नान एसी बसें खरीदेगी। वर्तमान में दिल्ली में 1490 कलस्टर बसिज चल रही हैं 2016-17 में कलस्टर योजना के अन्तर्गत 1000 नई और बसें जोड़ने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार वित्तीय दृष्टि से समृद्ध लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशुद्ध रूप से बाजार आधारित मॉडल पर प्रीमियम स्टेण्डर्ड की 1000 बसें भी शुरू करेगी। इन नई बसों को स्थान प्रदान करने के लिए रेवला, खानपुर, ढिंचाऊं कलां, खड़खड़ी नहर, बवाना सेक्टर-1 और द्वारका सेक्टर-22 में बीस डिपो बनाए जायेंगे। मैं बसों की खरीद और बस टर्मिनलों के विकास के लिए

325 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, 2016-17 के दौरान सराय काले खां और आनंद विहार अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों के जीर्णोद्धार व अन्य आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है जिसमें विश्वस्तरीय यात्री सुविधा प्रदान की जायेंगी। द्वारका में एक नया आईएसबीटी बनाने का प्रस्ताव है पीपी मोड में 1397 नये बस क्यू शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है। हमारी सरकार दिल्ली में लास्ट मई कनेक्टिविटी के लिए ई-रिक्शा को दे रही है। चालू वित्त वर्ष में 3709 बैटरी चालित वाहनों और ई-रिक्शा मालिकों को सबसिडी के रूप में 4 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि दी गई। मैं परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के लिए वर्तमान में दी जा रही एकमुश्त 15 हजार रुपये की निर्धारित सबसिडी को बढ़ाकर 30 हजार करने का प्रस्ताव करता हूं दिल्ली में प्रयोग के तौर पर एक इलैक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है अगर हमें इसके बेहतर परिणाम मिले तो ऐसी और बसें हम चलायेंगे। इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में रोड टैक्स पर भुगतान में छूट प्रदान की जाएगी। दिल्ली मैट्रो से करीब 27 लाख यात्री रोजाना सफर करते है ये संख्या दिसम्बर 2016 में मैट्रो परियोजना का तीसरा चरण पूरा होने के बाद 27 लाख से 41 लाख पर पहुंच जाएगी।

तीसरे चरण का एक और कोरिडोर जहांगीरपुरी से बादली नवम्बर 2015 में चालू किया जा चुका है और 2016-17 में 93 मार्गों पर मैट्रो फीडर बसों के बेड़े में 248 नई बसें हम शामिल करेंगे और उनकी संख्या अब बढ़कर 517 हो जाएगी। मैं 2016-17 में डीएमआरसी के लिए 763 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं। डीटीसी बसों, मैट्रो रेल, कलस्टर बसों में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए कॉमन मोबीलिटी पेमेंट कार्ड के अतिरिक्त सभी बसों

में इलैक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीनें लगाई जायेंगी। हम प्रत्येक बस स्टॉप पर एक यात्री सूचना प्रणाली भी लगायेंगे जो कि बसों की वास्तविक समय स्थिति और उनके पहुंचने की संभावित समय को प्रदर्शित करेगी। मैं परिवहन क्षेत्र के लिए 1735 करोड़ रुपये का योजना बजट प्रस्तावित करता हूं जो 2016-17 में कुल योजना परिव्यय का 1.4% है।

अध्यक्ष महोदय, पबिलक ट्रांसपोर्ट, जब हम परिवहन को देखेंगे तो सड़क से अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक अलग सेक्टर के रूप में देखा जाता है इसलिए मैंने इसका बजट प्रस्ताव अलग रखा लेकिन मैं चाहूंगा कि सदन इसको रोड ट्रांसपोर्ट से रोड इन्फ्रास्ट्रचर से जोड़कर देखे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड्स के बिना तो हो नहीं सकता तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि रोड्स और बसिज इन सबके नाम खर्च कर रहे हैं। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए तक बारापूला नाले पर ऐलिवेटिड रोड का दूसरा चरण 2016-17 में चालू हो जाएगा। बारापूला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार तक ऐलिवेटिड रोड के तीसरे चरण का कस्ट्रक्शन 1261 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है और इसे दिसम्बर 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दोनों परियोजनाओं के लिए मैं 400 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूं। दिल्ली में एक और महत्वपूर्ण योजना जिस पर सरकार काम कर रही है और बहुत ही एंबीशियस योजना है जो दिल्ली मैट्रो के जितनी एंबीशियस है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भरोसेमंद बनाने के लिए और मैट्रो की तरह से एक तरह से उसको ईजी कंफर्टेबल बनाने के लिए सरकार दो ऐलिवेटिड बीआरटी कोरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनमें से एक आनंद विहार से पीरागढ़ी तक यानि की पूर्वी पश्चिमी कोरिडोर

29 किलोमीटर का और दूसरा वजीराबाद से एयरपोर्ट तक उत्तर दक्षिण कोरिडोर 24 किलोमीटर तक का बनाने का प्रस्ताव है। मैं फिर से कह रहा हूं ये दोनों कोरिडोर अपने तक यूनिक स्टाइल में दिल्ली के सामने आयेंगे और ये उतने ही इम्पोंटेंट और उतने ही महत्वपूर्ण हो जायेंगे दिल्ली के लिए जिस तरह से मैट्रो लाईन दिल्ली की लाइफलाईन बनती जा रही है, अन्य चार मार्गों पर ऐलिवेटिड कोरिडोर एनएच-24 बाइपास से लोधी रोड तक एक भूमि का सुरंग और खजूरी खास से भौपुरा बार्डर तक कोरिडोर इंप्रूवमेंट जैसे कार्य आदि 2016-17 में शुरू करेंगे। कोरिडोर इंप्रूवमेंट की फिजिबलिटी स्टडी कराने के लिए कंसलटेंट्स की नियुक्ति कर दी गई है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम हो रहा है और ये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए यूटी पैक को भेजा गया है। पूर्व-पश्चिम और उत्तर दक्षिण जिन दो कोरिडोर मैंने पहले जिक्र किया, इनके सफल कार्यान्वयन के बाद इस मॉडल को पूरी दिल्ली में अपनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कोलंबिया में बरबटा के मेयर एनरिक पेनलोसा का। मैंने पिछले बजट भाषण में जिक्र किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दुनिया में सबसे अंडरस्टेंडिंग वाले सबसे विद्यमान लोगों में से माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम परिवहन की बात करें तो मैं कहूंगा कि एक महान शहर वो नहीं है जिससे राजमार्ग हों बल्कि वो है जहां एक बच्चा भी ट्राई साइकिल पर आराम से सुरक्षित जा सके ये उनका स्टेटमेंट है। हमारी सरकार सड़कों के डिजाइन संबंधी और हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? बार-बार हमने साइकिल चलाई, कार फ्री डे मनाया, ऑड-ईवन में हम साइकिल चलाकर जाते थे। बार-बार ये सवाल उठता था कि साइकिल के लिए कैसे, साइकिल ट्रैक नहीं है। हमारी सड़कों के डिजाइन में प्रोब्लम है हम उनके

डिजाइन जो हैं, उसको करेक्ट करेंगे। उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए और पैदल या साइकिल सवारों के अनुकूल बनाने के लिए सड़कों का रिडिजाइन और स्ट्रीट स्कीपिंग की तैयारी कर रही है। सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग को बढ़ावा देने और मार्गों को पैदल यात्रियों और विकलांग जनों के अनुकूल बनाने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान प्रयोजित योजन के रूप में 11 सड़कों की रिडिजाइनिंग हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस परियोजना के अंतर्गत सड़कों को सुसज्जित करने के लिए ग्रास-लिफ्ट्स शौचालय, पौधारोपण सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइट और इन्वर्टर हार्वेस्टिंग प्रणाली के काम करने के काम किए जायेंगे बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार जो अभी 11 सड़कों पर है, उसका 1260 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी की सभी सड़कों के लिए किया जायेगा। आउट रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, उस के दोनों तरफ एक प्रतिबद्ध एन.एम.वी. लेन यानि की साइकिल ट्रैक और फुटपाथ बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा इसका प्रस्ताव है। मैं सड़क ढांचा क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 में 2208 करोड़ रुपये की योजना बजट प्रस्तावित करता हूं जो कुल योजना व्यय का 11% है तो इस तरह से आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जोकि रोड भी उसका हिस्सा है 11% यहां पर और 8.4% परसेंट वहां पर तो लगभग 20% के करीब हम लोग इस पर खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, पॉलूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब चीजें इन्टीग्रेटिड है इनको अलग करके नहीं देख सकते। सरकार दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफी चिंतित है। हमने अल्पावधि यानि शार्ट टर्म और लांग टर्म दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण को कम करने के अनेक उपाय शुरू

किए है शक्ति शुरू की है। रियल टाइम बेसिज पर प्रदूषण के स्तर की निरंतर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है और पॉल्यूशन फैलाते घुमिए शहर में। दिल्ली में 6 एंबीऐंट ऐयर क्वालिटी मानिटरिंग सेन्टर बनाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 9 करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल एंबीऐंट ऐयर क्वालिटी मानिटरिंग वैन शुरू करेंगे ताकि निगरानी ठीक से रखी जा सके।

अध्यक्ष जी, ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण की समस्या जा बढ़ रही है, शहर की सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने और प्रदूषण में कमी लाने के लिए जागरूकता पैदा करने के वास्ते हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। हर महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है जिसका श्रेय मैं चाहूंगा इस सदन की तरफ से जोरदार स्वागत के साथ में गोपाल जी जो हमारे परिवहन मंत्री है, उनको दिया जाए। निरंतर उसको सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। जनवरी 2016 के पहले पखवाड़े में इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं ऑड ईवन फार्मूला को प्रयोग के तौर पर लागू किया और 15 अप्रैल से अप्रैल महीने में 2016-17 में इस कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष जी, वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कंपोनेंट में सड़कों पर चलने वाले वाहनों से उठने वाली धूल बहुत बड़ी समस्या है, झाड़ू लगाने के दौरान धूल के सूक्ष्म कण उड़ते है और उसके बाद हवा में फैले रहते हैं। एक नए कार्यक्रम एक नई योजना सरकार शुरू कर रही है सड़कों का व्यापक रख-रखाव के तहत और उसमें सड़कों को मशीनों से वैक्युम क्लीनिंग स्ट्रीट फर्नीचर और संकेतों की नियमित धुलाई जो वहां पर होता है और मलबे कचरे को मैक्नाइज स्वीपिंग

के जरिए बायोडिग्रेबिल डिस्पोजल बैग में इक्ट्ठा करना और फुटपाथ या भूमिगत मार्गों की समय-समय पर धुलाई सिविल, इलैक्ट्रिकल और बागवानी संबंधी ये सब उसमें एक तरह से इंटीग्रेटिड रहेंगे तो सड़क जब साफ हो तो साफ रहे और सड़कें जब साफ हों तो धूल न उड़े पॉलूशन न फैले, डस्ट लोगों के शरीर में न जाए। इसको देखते हुए ग्रीन बनाना उनको पूरी तरह से और वहां जो धूल उड़े सफाई में और फिर वहां दोबारा से न फैले लोगों के लंग्स में न जाए इसकी एक पूरी इंटीग्रेटिड योजना बनाई है और इसके लिए वर्ष 2016-17 में मैं 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रख रहा हूं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए हर रोज 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली दो सीएनडी कचरा प्रचालन यूनिटें लिबासपुर और टीकरी बोर्डर पर लगाई जायेंगी। अध्यक्ष जी, प्रदूषण के स्तरों और जन जागरूकता संदेशों लोगों को यातायात संबंधी जानकारी से लगातार अपडेट रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हम एलईडी स्क्रीन्स भी लगवा रहे हैं। मैं वर्ष 2016-17 में इस कार्यक्रम के लिए 137 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी जैसा कि मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सब पर तो है ही लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहां के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है कि नहीं करती है। अगर किसी शहर में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो आप दुनिया के सारे स्मार्ट सिटि में नम्बर वन पर ले आइए। उसको कोई आदमी स्मार्ट सिटी नहीं मान सकता। किताबें मान सकती हैं, डेटा मान सकता है लेकिन लोग नहीं मान सकते हैं उसको। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति का पैमाना इस बात को मानता हूं कि महिलाओं की कितनी प्रगति हुई

है। अध्यक्ष जी, हमने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाए किए है, चार महत्वपूर्ण उपाय जिनका मैं जिक्र यहां करूंगा। डीटीसी की 200 बसों में सीसीटीवी कैमरे हम पहले लगा चुके है, डीटीसी बसों में प्रयोग के रूप में वाई-फाई सेवा दिसम्बर 2015 में शुरू की गई थी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारी डीटीसी और कलस्टर बसों में आगे वाई-फाई सेवा और जीपीएस और सीसीटीवी कैमरों की हरेक बस में सुविधा की जाएगी। सरकार ने टैक्सियों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए जीपीएस प्रणाली अनिवार्य बना दी है ताकि वाहनों की लोकेशन का पता लगाया जा सके। हमने बसों में सतर्कता बनाने के लिए डीटीसी बसों में 4000 मार्शल भी तैनात किए है। सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समग्र सुरक्षा के लिए हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और निगरानी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं इसके अंतर्गत प्रारम्भिक बजटीय आबंटन के रूप में वर्ष 2016-17 के दौरान 200 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। हालांकि हम जानते है कि 200 करोड़ रुपये इतने बड़े टास्क के लिए बहुत कम है। उसमें पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी शुरू कर रहे हैं जैसे-जैसे स्टडी होगी और जैसे-जैसे मॉडल सामने आयेंगे हम इसमें और पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यह भी शहर को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दिल्ली पुलिस और गैर सरकारी संगठन सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर 421 मार्गों पर कुल 42 हजार डार्क स्पॉट्स की पहचान करी गई है। इन स्थलों पर प्रकाश का प्रॉपर अरेंजमेंट करने का काम वर्ष 2016-17 में पूरा कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी चीज है। इन चुने हुए स्थलों पर 42 हजार डार्क स्पॉट्स बड़ा टारगेट है ये। इन चुने हुए डार्क स्पॉट्स पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने के लिए 1216-17 के बजट में 114 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

दूसरा महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और प्रयोग किया है जो पहले उसमें बात कर रहे थे कि विमिन्स सिक्योरिटी फोर्स बनायेंगे महिला सुरक्षा दल बनायेंगे। इसमें प्रायोगिक तौर पर सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को मिलाकर एक मौहल्ला रक्षा दल का प्रयोग किया गया। इस प्रयास को स्थानीय नागरिकों और दिल्ली पुलिस और विशेषकर महिलाओं ने काफी तारीफ की कि ये काफी सक्सेसफुल है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी इम्पोंटेंट है। तो इस सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 2016-17 में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मौहल्ला रक्षक दल बनाने की स्थापना का मैं प्रस्ताव करता हूं और मैं दिल्ली के सभी मौहल्लों में, मौहल्ला रक्षक दल की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, द्वारका में, कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए 50 महिलाओं की क्षमता का छात्रावास 2016-17 में चालू हो जाएगा और 200 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए दिलशाद गार्डन, पीतमपुरा और वसंत गांव में तीन कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण 2016-17 में शुरू किया जाएगा। मैं महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 2016-17 में 1068 करोड़ रुपए की योजना बजट प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के ऐसे कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देन के लिए वचनबद्ध है, जिनके पास अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए आय के स्रोत नहीं हैं या बेहद कम है। सरकार करीब 6 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन, विकलांगता पेन्शन, राष्ट्रीय परिवार लाभ, नि:सहाय महिलाओं के लिए वर्ष 2016-17 में 975 करोड़ रुपये की वित्तीय

सहायता का प्रस्ताव करती है। वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार लाभार्थियों की जांच का एक व्यापक अभियान चला रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंदों तक पहुंचे और दोहरी सहायता लेने वाले या फर्जी लाभार्थियों का पता चल सकें। मैं यहां छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं पटपड़गंज से विधायक हूँ और पटपड़गंज का मैंने पेन्शन्स का डेटा डिपोर्टमेंट से लिया और उसको सिम्पल एक्सेल शीट में करके देखा कि कहां-कहां, किसके, क्या एड्रेस है क्योंकि विधान सभा के दौरान एक-एक गली, मौहल्ले से चुनाव और इन सब में वहां रहते हुए परिचय हो जाता है। सारा डेटा देखा, तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि चार-चार, पांच-पांच साल से ऐसे-ऐसे लोगों को पेन्शन मिलती है, मेरी विधान सभा के क्षेत्र के कोटे में या डेटा में जो मेरी विधान सभा क्षेत्र में रह ही नहीं रहे। उनका रजिस्टर्ड एड्रेस, जो हमारे सरकारी रिकार्ड में एड्रेस है, वो भी मेरी विधान सभा से बाहर का है और वो कोई पड़ोस का नहीं है। करवल नगर के एड्रेस की पेंशन चार साल पहले से चल रहा है। यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचे और दोहरी सहायता लेने वाले या फर्जी लाभार्थियों का पता चल सके, इसके लिए एकदम बहुत माइन्यूट लेवल पर स्क्रूटनी हम लोग करा रहे हैं। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि सरकार विभिन्न स्थानों पर नये वृद्धावस्था आश्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बताना चाहूँगा कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सभी पांच स्थानों अर्थात् कांति नगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में शुरू हो गई है। कांति नगर में वृद्धा आश्रम का निर्माण कार्य दिसंबर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य

रखा गया है। इसके अतिरिक्त गीता कालोनी, जनकपुरी, सरिता विहार, वसंतकुंज इनमें चार ओल्ड एज होम, मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए उस्मानपुर में पुरुषों के लिए और दल्लुपुरा में महिलाओं के लिए दो गृहों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

अध्यक्ष महोदय, रूजवेल्ट ने कहा था कि हमारी प्रगति की परीक्षा इस बात में नहीं है कि उन लोगों को और प्रदान किया जाये, जिनके पास पहले से प्रचुर है बल्कि प्रगति की परीक्षा इस बात में है कि जिनके पास बहुत कम है, उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने की व्यवस्था की जाये। सरकार युवाओं विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध युवाओं को प्रशिक्षण के जरिये बेहतर शिक्षा और कौशल करने की दिशा में काम कर रही है। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्टेशनरी खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस की अदायगी आदि लागू रहते हैं। इन सभी कल्याणकारी योजनाओं और अनुसूचित जाति बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए इस वर्ष मैं 398 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। 2016-17 में सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए कुल 1381 करोड़ रुपये के योजना बजट का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण सैक्टर है पानी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है वाटर एंड सीवेज। अध्यक्ष जी, पीने का साफ पानी सब को

चाहिये। वो राजा हो या रंक हो और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराये। हमने हर घर को 20 किलोलीटर पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराने का जब फैसला किया तो इसके पीछे लक्ष्य था कि समाज के निचले तबके को लाभ पहुँचे और साथ-साथ एक और लक्ष्य था कि नागरिक जब इसको एक कैंप में खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर बचाने की प्रवृत्ति भी लागू हो तो निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग से जुड़े हुए करीब 10 लाख परिवार सरकार के पानी बचाने के इस अभियान से जुड़े और इन्होंने बचाया है। अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा डेटा आपके सामने रख दूं कि पानी तो बचा ही, साथ-साथ में जब हमने यह फ्री पानी की स्कीम लागू की तो कहा गया कि यह सरकार तो सब्सिडी सरकार है, सारा फ्री में दे रही है लेकिन कपिल भाई जब अपनी बात रखेंगे किसी समय इस सदन में, वो पूरे विस्तार से रखेंगे कि पानी के बिल के कलैक्शन से इस योजना में, क्योंकि लोगों ने पानी बचाना शुरू किया और जो भी पानी 20 हजार किलोलीटर के नेट से बाहर गया उसकी बिलिंग हुई, इस योजना का फायदा उठाने के लिए जिन लोगों ने वर्षों से मीटर नहीं लगवाये थे, वो लोग अपने यहां मीटर लगवाने के लिए आगे आये और इस सब का फायदा यह हुआ कि पानी के बिल के कलैक्शन में इस बार रेवेन्यू कलैक्शन में 178 करोड़ रुपये एक्सट्रा कलैक्ट हुए हैं। यह एक नई इकनोमिक्स है कि जनता को फायदा भी पहुँचाओ, कलैक्शन भी बढ़ाओ और जो इंसपेक्टर राज है उसको भी खत्म करो। जनता खुद आगे आ रही है, अपना पैसा देने के लिए। मीटरिंग नेट में बड़ी योजनाएं चलाई गई कि मीटर लगवाना है, जनता मीटर लगवा ले, नहीं लगवाये, हमने कहा 20 हजार लीटर तक का पानी फ्री है, लोगों ने कहा कि हम भी मीटर लगवायेंगे। हमारे

घर में मीटर नहीं है नापेंगे कैसे? तो उन्होंने लगवाने शुरू कर दिये। उस सब का फायदा यह हुआ कि कलैक्शन में 178 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा कलैक्शन हुआ है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ादी के इतने साल बाद हम देश के लोगों के लिए पीन के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमें इस सदन में बैठ कर पीने का पानी जो आपकी टेबल पर भी रखा हुआ है, हम भी बाहर पीने जायेंगे तो यह बोटल वाटर पीना पड़ता है। देश को राजधानी में बैठ कर अगर हमको बोटल वाटर पीना पड़े, हमारे घरों में पानी के लिए हमें फिल्टर लगाने पड़े, आर.ओ. लगाने पड़े तो यह बहुत प्रोब्लमैटिक है। यह चिंता की बात है कि हम कहां अपने दम पर खड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक है, बड़ा फैसला है जैसा भी अप इसको व्याख्यायित करें। लेकिन यह सबसे जरूरी फैसलों में से एक है दिल्ली के लिए कि दिल्ली की सभी अधिकृत अनधिकृत कालोनियों में पीने का साफ पानी दिसंबर 2017 तक पाइप लाइन के जरिये घरों में उपलब्ध करा दिया जायेगा। यह फैसला लेकर, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि ये टारगेट, ये वायदे हम किसी और से नहीं कर रहे, हम अपने आपसे कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे देश की राजधानी में पीने का साफ पानी हर घर में आना चाहिए। हम छोटे से थे, हम देखते थे कि बस टूटी खोलो और हाथ से लगा कर पानी पी लो। आज आप किसी से बात करो, चार गाली देकर चला जायेगा। कहेगा ये पानी पीऊँगा, मैं मरूँगा क्या? जो भी स्थिति हो गरीब से गरीब आदमी भी टूटी खोल कर पानी पीने से डरता है। हमारी पूरी कोशिश यह है कि दिसंबर, 2017 तक दिल्ली के घरों में टूटी से खोलकर साफ पीने लायक पानी पहुँचने लगे और यह हमने अपने लिए कमिटमेंट किया है। इसमें से वर्ष 2016-17 में

300 नई अनधिकृत कालोनियों में पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचाने की योजना है। मैं इस प्रयोजन के लिए 676 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हमारा मकसद है दिल्ली के लोगों तक साफ पानी पिलाना और टैंकर माफिया का सफाया करना। टैंकर माफिया जैसे हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स में है, वैसे ही पानी क्यों ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि टैंकर माफिया का भी राज चलता है। टैंकर माफिया का राज खत्म करना और घर-घर तक पीने का साफ पानी पहुँचाना, यह हमारी सरकार ने अपने लिए लक्ष्य रखा है और इस दिशा में हमने काम भी किया है। पिछले एक साल में 217 कालोनियों को पाइप लाइन के जरिये पानी के नेटवर्क से जोड़ा है, जो वर्षों से इंतजार कर रही थी। 167 किलोमीटर नई पाइप लाइन बिछाई, 19 किलोमीटर मौजूदा पाइप लाइन को बदला और पिछली सरकारों के कार्यक्रम को देखेंगे, उनके डेटा को देखेंगे तो यह अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमने अनधिकृत कालोनियों में पानी की सुविधा का विकास, एक बड़ा काम यह भी हो रहा था कि अनधिकृत कालोनियों में जहां-जहां सीवर लाइन डली, पानी की पाइप लाइन डली वहां पर डेवलपमेंट चार्जेज जो था, वो इतना हेवी था कि एक 50 गज के प्लॉट में, 30 गज के प्लॉट में रहने वाला आदमी इतने महंगे-महंगे रेट पर कैसे वहां डेवलपमेंट चार्ज देकर लगायेगा। फिर वो सोचता है कि जब तक चल जाये तीस-चालीस हजार क्यों देने पड़े? चला जायेगा पचास हजार क्यों देने पड़े तो उसको हमने रियलाइज करते हुए कि यह नहीं दे पायेगा। हम कागजों में कुछ भी लिखते रहें, नहीं दे पायेगा, इसलिए सरकार ने उसको 100 रुपये पर स्क्वेयर मीटर किया और एक गरीब आदमी के लिए बड़ी राहत थी और मैं डेटा के बेस पर कह रहा हूँ कि यह शुल्क कम

करने के बाद से एक लाख तीस हजार नये उपभोक्ताओं ने पानी का कनैक्शन लिया। इस योजना के प्रति जो भारी उत्साह लोगों ने दिखाया, इसके लिए हमने इसको अब आगे 18 जुलाई, 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के जल बोर्ड से लोगों की एक बड़ी शिकायत थी, हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, आंदोलन करने जाते थे, एज ए सिटिजन भी हम लोग देखते थे, बिल बहुत आ रहे हैं जी। गली-गली में लोग कहते थे साहब ये बिल बड़े आ रहे हैं। साहब, लूट मची हुई है। क्यों लूट मची हुई है? जी, खराब है मीटर। अब मीटर खराब हो, मीटर रीडर ने गलती की हो, मीटर तेज चलता हो, जो भी वजह हो लेकिन एक आम आदमी के घर में अगर तीन-चार लाख रुपये का बिल आ गया तो भले ही वो जानता है कि मैंने इतना पानी खर्च नहीं किया और उसके सर पर तलवार तो लटकी रहती है। सबसे बड़ी शिकायत थी पानी के विवादित बकाया बिल बहुत बड़ी शिकायत थी तो खराब मीटर, मीटर रीडर की कारस्तानी इन सब के चलते लोगों को, मैंने भी थोड़े दिन देखा, राखी भी मेरे पास बहुत बिल लेकर आई, 40-40, 50-50 हजार से लेकर कई-कई लाख रुपये तक के बिल लोगों के विवादित बकाया थे और हमने जा कर दिखवाया, झुग्गियों में रह रहे हैं, बीस मीटर के प्लॉट में रह रहे हैं, तीन लाख रुपये का बिल आ रहा है। अरे, स्वीमिंग पूल बनाकर रखा हो नीचे तब भी तीन लाख रुपये का बिल नहीं आ सकता। उसका रिजल्ट यह होता था कि आम आदमी परेशान रहता था। मीटर रीडर जाकर रिश्वत मांगता था, पैसे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। अब आप एक-एक मीटर रीडर के पीछे तो मंत्रियो की नहीं भेज सकते। रोजना नहीं भेज सकते, कैसे भेजोगे, किस-किस को भेजोगे तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए यह

विवादित पानी के जो बकाया बिल थे उनको माफ करने की योजना बनाई और ई, एफ, जी और एच श्रेणी की जो कालोनियां हैं उनमें 100% और डी केटेगरी की कालोनी में 75%, सी कालोनी में 50% और ए और बी की कालोनी में उपभोक्ताओं का 25% बिल राशि माफ करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही जो लेट पेमेंट चार्जेज थे, वो सब के पूरी तरह माफ कर दिये तो बिल पूरी तरह माफ किये जाने से निर्धन बस्तियों में रहने वाले लोग लम्बे समय से जो बोझ उन पर पड़ा हुआ था वो तो बहुत खुश हैं और समृद्ध क्षेत्रों के लोगों में भी बकाया राशि में इतनी कमी को देखते हुए काफी उत्सुकता दिख रही है बिल जमा करने की और राजस्व वसूल करने वाली जो हमारी मशीनरी है, वो भी इससे उत्साहित है। क्योंकि बट्टे खाते में से पड़े हुए जो पैसे थे, वो मिलने लगे और 20 करोड़ रुपये वसूली करने में उनको कामयाबी मिली है यह अलग से हमने कैलकुलेट किया।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह देखें तो पूरा, दो-तीन चीजें हो गई, 20 किलोलीटर तक पानी मुफ्त देना, पुराने विवादित बिल माफ करना इन तमाम योजनाओं का लाभ दिल्ली जल बोर्ड को यह भी मिला कि लोग आगे बढ़ कर अपने-अपने घरों में मीटर कनैक्शन लगवा रहे हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए घर में पानी का नया मीटर लगाने के लिए बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। इसके विपरीत मीटर लगवाने के लिए जो पिछली सरकारों के प्रयास थे, वो हमने देखे हैं कि नॉन रेवेन्यू वाटर, नॉन मीटर्ड हाउसेज बहुत ज्यादा संख्या थी, अब वो तेजी से घट रही है। अपने कामकाज के लिए वर्ष के अंदर हमने द्वारका, बवाना, ओखला में तीन प्रमुख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि पहले बंद थे, उनको चालू करते हुए पेयजल की उपलब्धता में 10-20 फीसदी की वृद्धि की

है। दिल्ली में अनियोजित विकास के कारण अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें पर्याप्त सीवेज डिस्पोजल सिस्टम स्थापित नहीं किया जा सका। हमारा कमिटमेंट है कि डी.जे.बी. समूची दिल्ली को सीवर प्रणाली प्रदान करने के लिए 2036 तक का इंतजार नहीं करेगी जैसा कि सीवरेज मास्टर प्लान में टारगेट दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि ऐसा प्लान बनाना ताकि 8-10 साल के अंदर में हम दिल्ली की सारी कालोनियों में सीवर भी बिछा सकें। हाल ही में मुनर नहर को क्षतिग्रस्त किए जाने से दिल्ली को पहली बार जल संकट का सामना करना पड़ा लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने जिस तरह निरंतर राउंड द क्लॉक शिकायत निवारण मैनेजमेंट, टैंकर डिस्ट्रिब्यूशन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और मैनेजमेंट के जो उपाय तेजी से किये, उससे संकट की जो ग्रेविटी थी, वो काफी हद तक रोक ली गई। मैं इस प्रयास के लिए इस सदन की तरफ से दिल्ली जल बोर्ड की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ, बहुत-बहुत सराहना करता हूँ। परंतु दिल्ली सरकार को इस दौरान यह भी एहसास हुआ कि वर्तमान में हमारा जल का फ्यूचर, पानी का फ्यूचर पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम दिल्ली जल बोर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक पूरी काम्प्रेहेन्सिव योजना बना कर लायेगा, तैयार करेगा और जो हमारे तालाब है, जोहड़ है इनके जीर्णोद्धार की नीति बनायेगा और ग्रीष्मकालीन कार्य योजना तैयार करके यह सुनिश्चित किया जा सके ताकि दिल्ली को पीने के पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मैं जलापूर्ति और सीवेज के लिए 1976 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कुल योजना व्यय का 9.6% है।

अध्यक्ष महोदय, बिजली में हमारा लक्ष्य आम आदमी के लिए सस्ती और कन्टीन्यूअस बिजली उपलब्ध कराना है। सरकार ने दरें कम रखने के

लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 2015-16 में विद्युत आपूर्ति पर कड़ी निगरानी और नियमित समीक्षा की बदौलत हम औसत लोड शेडिंग को 0.15% के स्तर पर बनाये रख सके, जो अब तक का सबसे कम रिकार्ड है। हमने अपना वायदा पूरा किया है और 400 यनिट तक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं अर्थात् कुल घरेलू उपभोक्ताओं के करीब 90 फीसदी परिवारों के बिजली के बिल 50% कम आ रहे हैं। पहली बार इस नीति का विस्तार हमने एनडीएमसी इलाकों में भी किया है। मैं दिल्लीवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 1600 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अनधिकृत कालोनियों में समयबद्ध तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों में सड़क और नालियां बनाने का काम डीएसआईआईडीसी को सौंप दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। अभी तक जो विकास का काम होता था, वो केवल 895 कालोनीज तक सीमित रहता था बाकी जगह काम तो होता था लेकिन जुगाड़ से होता था। एमएलए की चल जाये, नागरिकों की चल जाये, जिसकी जैसे चल जाये, जो जिस पर मेहरबानी कर दे, अथोराइज रूप से कोई भी किसी को कह सकता था, नहीं जी, यह तो लिस्ट में ही नहीं है तो हमने बकायदा डीएसआईआईडीसी को ऑर्डर करके कहा है कि दिल्ली की एक-एक अनअथोराइज कालोनी में डेवलपमेंट का काम करना है और अगले वित्त वर्ष में दिल्ली की, इसके लिए हमने टारगेट भी रखा है, अगले वित्त वर्ष में दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों में सड़क और नालियों का निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

एक भी कालोनी ऐसी नहीं बचेगी और इसके लिए डीएसआईआईडीसी को 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है यह भी पैसा अगर देखे क्योंकि जगदीश जी बैठे हैं और बाकी सदस्यों को भी आइडिया है कि अनअथोराइज्ड कालोनीज में डेवलपमेंट का काम 300 करोड़ रुपये में नहीं होने वाला है तो इसके लिए योजना यह बनाई गई है कि जितनी भी अधिक राशि चाहियेगी, वो डीएसआईआईडीसी अपने फंड से कर लेगा या लोन ले लेगा, बाद में सरकार उसको पेमेंट करेगी लेकिन डीएसआईआईडीसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि दिल्ली की सारी अनअथोराइज्ड कालोनीज में रोड कंस्ट्रक्शन का काम और ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया जाये इस साल के अंत तक। इसके अलावा जो अलग-अलग एजेंसियों को काम दिए गए थे, उनको वो एजेंसियां पूरा करेंगी, उसके लिए 190 करोड़ रुपये की अलग से राशि प्रस्तावित की जा रही है। यह उस 300 करोड़ में शामिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो रहा डेवलपमेंट का काम, लेकिन अनअथोराइज्ड कालोनीज को रेग्युलराइज करना, वो भी एक बड़ा काम है, इसके लिए हमने नये नियम बना दिये हैं और दिल्ली सरकार ने इन नियमों का अनुमोदन करके भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अधिसूचित करे ताकि ऐसी सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जो सके जिनमें 1 फरवरी, 2015 को 50% से अधिक निर्माण कार्य किया जा चुका हो। मैं उम्मीद करूँगा कि नेता, विपक्ष इसमें हमार मदद करेंगे। डेवलपमेंट काम तो हम पूरा कर लेंगे लेकिन जो यहां से नियम बनाकर भेजे गए हैं 1 फरवरी, 2015 को जहां 50% निर्माण कार्य था, वहां उन कालोनियों को रेग्युलराइज करने का जो प्रयास केन्द्र सरकार के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं केन्द्र सरकार से सम्पर्क में, उनसे वहां फैसला लिवाने में, मैं सदन के माध्यम से नेता, विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि उसमें भी वो मदद करें।

अध्यक्ष महोदय, अनअथोराइज्ड कालोनीज के साथ-साथ झुग्गी बस्तियों का विकास भी सरकार के लिए जरूरी है, दिल्ली के लिए जरूरी है। दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए 3 लाख मकानों की जरूरत है। हमारी सरकार ने दिल्ली स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास पुर्नस्थापना नीति तैयार की है इसके तहत् झुग्गी के बदले वैकल्पिक आवास पाने की पात्रता की जो नई कट ऑफ है, वो पहले 4 जून, 2009 थी, उसे बदल कर 1 जनवरी, 2015 किए जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली को स्लम मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने झुग्गीवासियों के स्थानीय पुनर्वास का कार्यक्रम यानी आम भाषा में कहें जहां 'झुग्गी वहां मकान' यह स्कीम शुरू की है। इसके तहत् पहले प्रायोगिक आधार पर क्योंकि अभी तक दूसरे कोने में जाकर मकान मिलता है, लोग नहीं जाते थे, तो हमने कहा जहां झुग्गी वहां मकान पहले चरण में हमने प्रायोगिक आधार पर तीन विधान सभा क्षेत्रों में 20 झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के स्थानीय पुनर्वास की योजना बनाई है। इसके बाद हम इस मॉडल का अनुकरण दिल्ली के अन्य भागों में भी करेंगे। इस प्रयोजन के लिए 2016-17 के बजट में डीयूएसआईबी के लिए सीड मनी के रूप में 100 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान करने के लिए नये शौचालय के निर्माण और मौजूदा परिसरों के जीर्णोद्धार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी तक 93 शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनमें 30 नये ब्लॉक्स है और 63 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको रिडेवलप किया गया है। इससे कुल शौचालय सीट्स की संख्या 4500 बढ़ गई है। हमारी सरकार ने 2016-17 में सभी झुग्गी बस्तियों में जन सुविधा परिसरों के रूप में स्वच्छ शौचालय प्रदान करने का निर्णय किया है

और इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय प्रस्ताव करता हूं। मैं आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 2466 करोड़ रुपये योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं जो कुल योजना व्यय का 12% है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शिक्षा के बारे में कहा, मैं थोड़ा सी बात कला, संस्कृति के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शिक्षा को भी नियंत्रित नहीं करना चाहिए, प्रबंधित करना चाहिए। शिक्षा के लिए भी नियंत्रण नहीं प्रबंधन चाहिये, वैसे ही कला-संस्कृति के लिए भी नियंत्रण नहीं चाहिये, प्रबंधन चाहिये और हमने इसीलिए कला-संस्कृति को दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाने की ओर ध्यान दिया है, जो पहले सरकारों ने नहीं दिया। आपको ध्यान होगा अभी मैंने जब शिक्षा के प्रस्तावों में भी कहा था 8 करोड़ की राशि स्कूलों के 16 लाख बच्चों के लिए आर्ट्स, कल्चर, थियेटर इन सब को प्रोमोट करने के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि का अलग से उनको ट्रेनिंग देने के लिए है लेकिन कला-संस्कृति पर हमारा और विशेष ध्यान है। हमारी कोशिश यह है कि जो अभी तक स्थापित बड़े-बड़े सभागार हैं, वहां तो ऐतिहासिक अच्छे कार्यक्रम हों ही, बल्कि वहां से निकल कर गली, मौहल्ले के पार्कों में, मौहल्ले के छोटे-छोटे ऑडिटोरियम्स में, मौहल्ले के छोटे-छोटे कम्युनिटी हॉल्स में ये कार्यक्रम वहां हो और वहां कला-संस्कृति पहुँचे, लोकलाइज सिस्टम हो वहां पर। देश के कोने-कोने से लोग आकर रहते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी-अपनी कला-संस्कृति का वहां विस्तार चाहते हैं। साहित्य कला परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ दर्जनों सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया। दिल्ली अभिलेखागार में एक और बड़ा काम कर रही है सरकार। दिल्ली अभिलेखागार ने जो हमारे अभिलेखे रिकॉर्ड्स थे, उनके

डिजिटलाइजेशन और माइक्रोफिल्मिंग की दिशा में काम किया है और पुरातत्व विभाग ने दिल्ली में 18 स्मारकों को संरक्षित किया और अग्रणी सड़कों पर स्थित 143 स्मारकों के संरक्षण की योजना बनाई है। अगले साल साहित्य कला परिषद शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में प्रतिभा की खोज के लिए व्यापक अभियान चलाएगी ताकि रंगमंच, संगीत, नाटक और कलाओं को स्कूली बच्चों में प्रोत्साहित किया जा सके।

मैं कला, संस्कृति और भाषा के प्रोत्साहन के लिए 2016-17 में 54 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। मैं इसी तरह से दिल्ली जो कि एक टूरिस्ट सिटी भी बने, नॉलेज सिटी के साथ-साथ हैपनिंग सिटी भी बने। हमने कहा कि हमने इंवेंट्स आयोजित करने के लिए फेसिलिटी ऐसी कर दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर दिल्ली में कोई कल्चरल या इस तरह की म्यूजिकल इवेंट आयोजित करना चाहता है तो कहीं से भी ऑन-लाईन एप्लीकेशन डाल सकता है, उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है पर जो हमारा पर्यटन विभाग था, मेरे उनसे काफी व्यक्तिगत संवाद भी हुए हैं, कपिल भाई उस विभाग को देख रहे हैं उनके माध्यम से भी हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की संस्कृति की व्यापक अनदेखी हुई है। ऐसा मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और पर्यटन पर जो ध्यान केन्द्रित किये जाने के उपाय थे, उनका नितांत अभाव रहा है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन एक जनरल अंडरस्टेंडिंग में अपनी बात कह सकता हूं कि डीटीडीसी का जो इस्तेमाल हुआ केवल पुल बनाने में, शराब विक्रेता संगठन बनाने के रूप में ज्यादा हुआ, टूरिज्म के प्रमोशन में कम हुआ। देखिये आज डीटीडीसी शराब बेच रहा है, आज डीटीडीसी पुल बना रहा है, आज डीटीडीसी

ये काम कर रहा है टूरिज्म पर क्या कर रहा है, बहुत परंपरागत आयोजन वही तो हमने इसको पूरे सिस्टम को चेंज किया है और दिल्ली में आने वाले टूरिस्ट और दिल्ली में और अलग-अलग काम से आने वाले लोग दिल्ली के टूरिज्म का, कल्चर का आनंद उठा सकें, इसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई गईं ताकि हम देश की राजधानी के रूप में गर्व के साथ कह सकें कि लोग देश की राजधानी में आ रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो गुड़गांव में होते थे, फरीदाबाद में होते थे, नोएडा में होते थे, हमारी योजनाओं की वजह से और हमारी सहजता की वजह से आज वो कार्यक्रम दिल्ली में हुए हैं और कई-कई वर्षों बाद हुए हैं या पहली बार हुए हैं। हमने छोटे-छोटे थियेटर्स में कार्यक्रम किये जैसा मैंने कहा अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में जहां करप्शन की गुंजाइश थी, उनको प्लग-इन किया। सरकार ने दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बताया। आज हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड आरक्रेस्टा में ए.आर.रहमान, जुबिन मेहता के मेगा-शो करवा रहे हैं। I.G.N.C., Disney Beauty or Beast, Coalition creative Industry Festival पूर्वोत्तर उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। आने वाले वर्ष में सिंगल विंडो क्लीयरेंस को जारी रखते हुए हम रेस्टोरेंट और हॉस्पिलिटी उद्योग के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे ताकि ये इंडस्ट्री और फल-फूल सके। धर्म, भाषा, क्षेत्र और व्यवसाय की विविधिता के साथ दिल्ली भारत के बहु-सांस्कृतिक और मिश्रित ताने बाने को प्रस्तुत करती है। हम दिल्ली फेस्टिवल नाम से एक विश्वस्तरीय उत्सव की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं । ये ऐसा उत्सव होगा जो दिल्ली के लोगों की भावनाओं का सम्मान बढ़ाएगा और नागरिकों में गौरव जगाएगा। ये उत्सव हमारी शापिंग संस्कृति, हमारे खानपान,

हमारे संगीत, भाषा, रंगमंच और फिल्मों का एक मिला-जुला उत्सव होगा 'दिल्ली फेस्टिवल'। हमारी सरकार ब्रांड दिल्ली नाम का एक अभियान शुरू कर रही है। हम वेबसाइट, एप्स, मेप्स, सोशल मीडिया और माइक्रोसाइट्स के जरिए टूरिज्म स्पॉट के रूप में दिल्ली की ऑनलाइन मौजूदगी को दर्ज करवाएंगे और 2016-17 में दिल्ली ब्रांड और दिल्ली फेस्टिवल के लिए मैं 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। 2016-17 में एक और प्रस्ताव कुतुब मिनार मेट्रो स्टेशन से कुतुब मिनार तक एक स्काइ-वॉक-वे बनाने का प्रस्ताव है यानि की आप मेट्रो पर उतरिए और वहां से स्काईवॉक करते हुए कुतुब मिनार तक पहुंचिये। ये महरौली पुरातत्व परिसर के ऊपर से जाएगा। मैं 2016-17 में पर्यटन ढांचे के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्षा महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और देश का सांस्कृतिक हृदय है, फिर भी गतिशील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारे जो एंट्री पाइंट्स हैं, वो डायनमिक नहीं हैं। जो लोग यहां आते हैं, उनको ऐसा अहसास हो कि वो देश की राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए जो डी.टी.डी.सी. है, वो शहर की सीमाओं का जीर्णोद्धार करेगा और उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड प्रमीशन थी, वो हमें मिल गई हैं और सड़क मार्ग से गाजीपुर, धौलाकुंआ जैसे जो हमारी एंट्री प्वॉइंट्स हैं, उनका सौन्दर्यीकरण करने की हम इस साल योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने वक्तव्य का भाग 'ख' प्रस्तुत करता हूं :

अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण के भाग 'क' में मैंने सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और मैं एक बार फिर दृढ़ता के साथ कहता हूं कि

यह सरकार दिल्ली के आम आदमी द्वारा और आम आदमी के लिए है। करों और शुल्कों के रूप में दिल्ली के लोगों से वसूल किया गया एक-एक रुपया अत्यंत ध्यानपूर्वक और ईमानदारी और निष्ठापूर्वक यह सरकार खर्च करती है, पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। ये धारणा सही नहीं है कि केवल बहुत अमीर लोग ही टैक्स देते हैं। अगर हम बहुत गहनता से देखें तो शहर में रहने वाला गरीब से गरीब आदमी यहां तक की एक भिखारी भी टैक्स देता है, जब वो बाजार से माचिस खरीदने जाता है, नमक की थैली खरीदने जाता है तो वो भी टैक्स देकर आता है। सरकार उसके टैक्स का भी उतना ही सम्मान करती है जितना एक लाख या एक करोड़ रुपये देने वाले टैक्सपेयर का करती है, वो भी सरकार के लिए एक टैक्सपेयर है। हमने जितने भी अभी टार्गेट्स रखे सरकार के लिए, जितनी योजनाएं रखीं, उसके लिए हमें रिर्सोसेज चाहिए, होंगे, अतिरिक्त रिर्सोसेज चाहिए होंगे। वहीं हम न्यायोचित, निष्पक्ष और स्थिर टैक्स स्ट्रक्चर के भी पक्षधर हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पारदर्शी, ईमानदार और प्रभावकारी शासन की बदौलत समग्र राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस उपलब्धि का श्रेय उच्चतम स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने, ईमानदारी से सरकार चलाने और उन स्तरों पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जाता है, जहां नागरिकों का संपर्क सरकार के साथ होता था वहां टेक्नोलॉजी अब संपर्क कर रही है, अब रिश्वत की गुंजाइश कम हो गई, दलालों की गुंजाइश कम हो गई। संवेदनशील पदों पर हमने ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। कम लागत पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने और फिजूलखर्ची को रोकने की इसमें अहम भूमिका रही। यहां इस बात की भी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि किस तरह से साढ़े तीन करोड़ में बनने वाले फ्लाईओवर ढाई सौ करोड़ में

या उससे कम में पूरे हो गये। 24 करोड़ में बनने वाला आईटीआई कैसे 16 करोड़ में पूरा हो गया, वो क्या इक्नॉमिक्स है अब लोगों का पूरा ध्यान जा रहा है इस तरफ लेकिन कर-राजस्व वैट की प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसकी जो कुल वसूली सरकार की है, उसमें 65% उसका कंट्रीब्यूशन है और हमारी अधिकतर डवल्पमेंट की जो गतिविधियां हैं, मुख्यरूप से वैट से प्राप्त होती हैं। मेरा कराधान प्रस्ताव निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।

हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दिल्ली के व्यापार के डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टर को क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव करेक्टर रखती है उसको बनाकर रखना। हमारी टैक्स पॉलिसी का दूसरा सिद्धांत है वर्तमान व्यवस्था को सरल बनाना ease of doing business को हर तरफ से प्रोत्साहन देना। तीसरा सिद्धांत है अलग-अलग आईटम्स के अलग-अलग लिस्ट में जो मल्टीपल एंट्रीज से पैदा कन्फ्यूजन है, उससे रिश्वतखोरी भी बढ़ती है बेईमानी भी बढ़ती है व्यापारी को भी चोरी करने का, गड़बड़ी करने का स्कोप मिलता है। सरकार के अधिकारियों को कर्मचारियों को भी रिश्वत लेने का स्कोप मिलता है तो इन आइटम्स की मल्टीपल एंट्रीज से उनको ईजी करना और हमारी चौथी कोशिश है टैक्स की दरें पड़ोसी राज्यों की दरों से या तो समान हों या कम हों। मिठाइयां, नमकीन, घडियां और रेडीमेड गारमेंट्स जैसी कई एसी वस्तुएं हैं, जिन पर पड़ोसी राज्यों में कर की दरें कम थीं। इससे विषम स्थिति पैदा होती है हमने वैट ढ़ाचे में इस तरह के असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है। जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसका अंतिम जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसका अंतिम सिद्धांत सबसे

महत्वपूर्ण यह है कि हमने वॉलियेंटरी कंप्लायेंस, इनफोर्समेंट नहीं, वॉलियेंटरी कंप्लायेंस, इनपार्टीसिपेटरी कंप्लायेंस को हम महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं इसमें। मैं अपने टैक्स रिफॉमर्स को दो हिस्सों में प्रस्तुत करूंगा, एक वैट में कमी, वैट के रेट्स में कहां-कहां कमी आ रही है लाने का प्रस्ताव है और दूसरा जो टैक्स का रेसनलाईजेशन है, वो कहां-कहां प्रस्तावित है। हमारी सरकार आटोमोबाइल्स के कारण बढ़ते प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है। बैटरी से संचालित यातायात के साधनों जैसे ई-रिक्शा, बैट्री प्रचालित वाहनों, हाईब्रिड आटोमोबाइल्स अन्य ईंधन विकल्प के साथ बैटरी संचालित पर वैट की दर साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मिठाइयों और नमकीन पर, बड़ी मिठाइयां खिलाते हैं सब, हर खुशी में मिठाई चाहिए, लड्डू चहिए, मिठाइयों और नमकीन पर वर्तमान में साढ़े बारह प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है जबकि हरियाणा और यूपी में इन पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगता है तो इसकी वजह एक से टैक्स टैक्स अर्बिटाइज पैदा होता है, मैं मिठाइयों और नमकीनों पर वैट की दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। वर्तमान में पांच हजार मूल्य तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिश्त और उससे ज्यादा पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से कर लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों में सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगता है। मैं इस विसंगति को दूर करने के लिए सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। दिल्ली में मार्बल जो वर्तमान में अर्निष्ट वस्तु होने के नाते साढ़े बारह प्रतिशत कर लगता है, वो किसी में लिस्ट्ड नहीं है। मार्बल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ दिल्ली ने लोगों को केवल

दिल्ली के व्यापारियों से मार्बल खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए क्योंकि अभी सब बाहर से ले आते हैं और टैक्स बाहर चला जाता है। इसके लिए मार्बल पर कर में कमी लाने का अनुरोध किया था और मैं समझता हूं कि ये एक प्रेक्टिकल डिमांड है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको मार्बल पर कर की दर साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना राजस्व के हित में भी होगा और मैं इसका प्रस्ताव रखता हूं।

अब मैं आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय rationalize syntax rationalization 49.12.9 के प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली में घड़ियों पर अलग-अलग दरों से कर लगता है जो पांच हजार मूल्य तक की घड़ियों पर साढ़े बारह प्रतिशत, पांच हजार से ऊपर की घड़ियों पर बीस प्रतिशत और पड़ोसी राज्यों में सभी प्रकार की घड़ियों पर साढ़े बारह प्रतिशत का है। अध्यक्ष महोदय, उसका नुकसान यह होता है कि जो बहुत महंगी-महंगी ब्रांडेड घड़ियां हैं, उनपर कई लोगों ने अपना-अपना अनुभव बताया कि आप व्यापारी के पास जाइये वो आपको कहेगा हां जी, घड़ी ले लो अगर आपको तीस-चालीस हजार रुपये सस्ती चाहिए तो कल ले जाना पैसे दे जाओ, टैक्स दूसरे राज्यों से कटकर आ जाता है, बिल दूसरे राज्यों से कटकर आ जाता है। हमारे अधिकारियों ने कई बार रिपोर्ट किया है इस चीज को तो इसलिए इस आर्बिटाइज को भी खत्म करने के लिए मैं सभी प्रकार की घड़ियों पर साढ़े बारह प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। टैक्सटाइल और फैब्रिक वर्तमान कर अनुसूचियों में अलग-अलग एंट्रीज में कवर होते हैं जिनमें से कुछ टैक्स-फ्री में आते हैं जबकि बाकी अधिकतर पांच प्रतिशत की दरों में आते हैं इसकी वजह से भी आर्बिटाइज फैलता है मैं इस प्रणाली को सरल बनाने के लिए

खादी और हैण्डलूम के वस्त्रों को छोड़कर सभी प्रकार के टैक्सटाइल और फैब्रिक पर पांच प्रतिशत की समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। प्लास्टिक वेस्ट अभी तक टैक्स फ्री रहा है जबकि कच्चे प्लास्टिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक दाना प्लास्टिक पाउडर, प्लास्टिक की बड़ी खेप मास्टर बैचेज पर पांच प्रतिशत का कर लगता है। प्लास्टिक वेस्ट को चूंकि रि-साईकिल करके प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मैं प्लास्टिक वेस्ट पर भी पांच प्रतिशत की समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में इन्वर्टर्स और यूपीएस साढ़े बारह प्रतिशत की सामान्य नॉन-लिस्टेड अनिर्दिष्ट दर से कर योग्य हैं परन्तु कर योग्य वस्तुओं की अनुसूची में यूपीएस युनिट्स से एक डुप्लीकेट में एंट्री है। इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और टैक्स चोरी भी होती है और व्यापारियों का शोषण भी होता है, मैं इस एंट्री को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में पांच सौ रुपये से ऊपर के फुटवेयर पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से कर लगता है मैं फुटवेयर पर कर की दर को तर्कसंगत बनाने के लिए सभी प्रकार के फुटवेयर पर पांच प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। वर्तमान में स्कूली बच्चों के लिए एक और घोषणा उपयोगी हो सकती है, तीन सौ रुपये तक के अधिकतम एमआरपी वाले स्कूल बैग पर पांच प्रतिशत और तीन सौ रुपये से जैसे ही उसका रेट बढ़ता है, उस पर साढ़े बारह प्रतिशत का कर लगता है। मैं स्कूल बैग पर कर की दर को तर्कसंगत बनान के लिए उनके मूल्यों पर विचार किये बिना सभी प्रकार के स्कूल बैग्स पर पांच प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। लौह और अलौह धातुओं की वर्तमान एंट्री के अंतर्गत एल्यूमिनियम या मैटल सीट्स का उल्लेख नहीं है

और कुछ वस्तुओं पर साढ़े बारह प्रतिशत की उच्चतर दर से कर लगाया जाता है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए मैं तत्संबंधी एंट्री को निम्नांकित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। लौह और अलौह धातु और उनकी सींटें, परतें निष्कर्षण सहित उनके मिश्रण अलौह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता आदि शामिल हैं ये मैं उसको लिस्टिंग करता हूं।

अध्यक्ष जी, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद पर वर्तमान में बीस प्रतिशत की दर से कर लगता है इससे संबंधित जो एंट्री है, वो इस तरह से है कि tobacco & gutka unmanufactured tobacco, bidies and tobacco used in manufacture or bidies and hukka tobacco इसका दायरा और बढ़ाने के लिए मैं इसको संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें हम लिख रहे हैं umnanufactured tobacco, tobacco and tobacco products in all forms such as cigarette irrespective of form a length क्योंकि वो लेन्थ के हिसाब से थी chewing tobacco, गुटका, सिगार, हुक्का तम्बाकू, खैनी, जर्दा, सुरती, बीड़ी इत्यादि तो इसमें इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ जाएगा। वैट की दरों से संबंधित सुधारों के अतिरिक्त सरकार ने जैसा मैंने कहा कि जनता की भागीदारी को अधिक बल दिया है इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे वैट विभाग ने शुरू की है, वैट विभाग के अधिकारियों ने, इसका नाम है ''बिल बनाओ इनाम पाओ'' इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में कोई भी उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदते वक्त खुदरा बिल यानि इन्वाइस का स्नेपशॉट लेकर अपने मोबाइल ऐप के जरिए सरकार को हमारे वैट विभाग को भेज सकता है। इस कार्यक्रम ने इस योजना ने एक नई ऊर्जा लोगों में पैदा की है कि आप बिल बनवाइये और बिल के पांच गुना तक का अधिकतम पचास हजार

रुपय तक का इनाम पाईये। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2016 के दौरान हमें आठ हजार एंट्रीज मिली जबकि जनवरी 2016 में चार हजार एंट्रीज प्रापत हुई थीं। ये लगातार पापुलर हो रही है और मैं स्वयं इसके कार्यक्रम में उपस्थित था, ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, किसी महिला ने अपने बच्चे के लिए दो सौ रुपये की दवाई खरीदी उसको अब पांच गुणा राशि इनाम के रूप में मिली। किसी ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी के लिए ज्वैलरी खरीदी उसको पचास हजार की राशि इनाम के रूप में मिल रही है जो महंगी ज्वैलरी है तो इस तरह से समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं लेकिन सरकार को इसका क्या फायदा है या मैं कहूं कि जनता को ओवरआल क्या फायदा है हम सरकार में लॉटरी तो चला नहीं रहे इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो व्यापारी जनता से सरकार के बिहाफ पर टैक्स कलैक्टर के रूप में कार्य करता है वो टैक्स की चोरी न कर पाए, कैसे कर रहा है, जनता से टैक्स ले रहा है जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गये सौ रुपये का बर्गर खरीदा रेस्टोरेंट में उसका बिल आता है एक सौ बारह रुपये का, कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए सौ रुपये की खरीदी, एक सौ बीस रुपये की आई अब वो बीस रुपये या बारह रुपये जनता से तो ले लिये लेकिन शाम को टैक्स की एंट्री अपनी मशीन से उड़ा दी और वो सौ रुपये का बर्गर एक्चुअली एक सौ बारह में बेचकर बारह रुपये भी अपने पास रख लिये तो जनता से ओरिजनल कंटेंट का पैसा भी ले लिया और बारह रुपये या बीस रुपये जो टैक्स के लिये, थे वो भी ले लिये और अपने पास चोरी करके रख लिया सरकार को नहीं दिया। ये तो जनता के साथ बहुत बड़ी चीटिंग है। इसका फायदा ये हो रहा है कि हमें जो बिल आ

रहे हैं, हमारे पास में वो एक तरह से हमारी इंटेलीजेंस युनिट का काम कर रहे हैं। एक-एक आदमी जो बिल भेज रहा है वो इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा है और वहां से मिली इन्फार्मेशन के बेस पर पिछले महीने करीब-करीब एक करोड़ रुपये का टैक्स एक्स्ट्रा वसूला गया है जो इंटेलीजेंस और अभी तो कई करोड़ रुपये के टैक्स के बिलों पर जांच चल रही है। कई कंपनियां जिनके टैक्स नंबर खत्म हो चुके थे, फर्जी टिन नंबर थे, ऐसी कंपनियों को पकड़ने में हमें सहायता मिली है तो ये एक अलग महत्वकांक्षी योजना है हमारे टैक्स विभाग की। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत बाजार और व्यापार संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से ऊपर राजस्व में योगदान करते है, ऐसे संगठन वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक और ऊपर अर्जित राजस्व का दस प्रतिशत प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्व में सर्वाधिक योगदान करने वाले दस शीर्ष बाजार संगठनों को भी प्रत्येक को पांच-पांच लाख रुपये का मार्किट एसोसिएशन को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि का इस्तेमाल बाजार के समग्र सुधार और जन-सुविधाओं के रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण, मरम्मत आदि कार्यों पर किया जाएगा ये एक महत्वपूर्ण योजना है कि जो व्यापारी संगठन ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वो अपने वहां माहौल बनाएं, टैक्स दें और जो निर्धारित राशि है जो एक फिगर उनके लिए तय की गई उससे ऊपर अगर आएगा तो उसमें उनको ईनाम दिया जाएगा। वहां उसको खर्चा किया जाएगा, वहीं लोकल भी खर्चा किया जाएगा और उनको ईनाम दिया। उसके लिए, वहां डवल्पमेंट पर खर्च किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, ऊपर दिये गये इन तमाम ब्यौरों से स्पष्ट है कि हमारी सरकार अतीत में जो कमांड की नियंत्रण का, बाजार में घुसपैठ करने वाली परंपरागत पद्धतियां थीं सरकार चलाने की उनसे

अलग-अलग काम कर रही है और एक तरह से फेसिलिटिएट कर रही है व्यापारियों को उनका शोषण नहीं कर रही है उनके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं बिठा रही है। अब मैं आपके समक्ष उत्पादन शुल्क, स्टैम्प शुल्क और विलासिता कर से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं। पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में शराब के व्यापार को सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार दूर करने की बात कही थी आज मैं प्रसन्नता के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा शुरू किये गये उपायों के अनुकूल परिणाम आने लगे हैं।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने पिछले वर्ष शराब पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की थी परंतु आबकारी लीकेज रोकने के लिये, कमियां दूर करने के लिये हमने सिस्टमैटिक चेन्जेंज सदन के समक्ष अनुमति से लागू किये थे। हमने उत्पाद शुल्क लगाये जाने का बिंदु ट्रांसपोर्ट परमिट लेवल से हटाकर आयात परमिट लेवल पर स्थानांतरित कर दिया था। इसके कारण राज सरकार द्वारा किये गये अन्य सुधारों की बदौलत रेवेन्यू कलैक्शन में 31% का इजाफा हुआ और यह 2014-15 में तीन हजार एक सौ सत्तासी करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष चार हजार दौ सौ करोड़ रुपये पहुंच गया। इस प्रकार इंस्पेक्टर राज खत्म करने से हमें टैक्स कलैक्शन बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये मौजूदा सुधार ना केवल जारी रखे जायेंगे बल्कि कुछ और सुधार भी शुरू किये जाने की योजना है। विलासिता कर से राजस्व वसूली में 36.7% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष विलासिता कर में 322 करोड़ प्राप्त हुए थे जबकि इस वर्ष 440 करोड़ रुपये वसूली का अनुमान है। सरलीकृत कर व्यवस्था की दिशा में एक और कदम रखते हुये मैं लग्जरी टैक्स की ओर जाता हूं। मूल्यांकन आकस्मिक आधार पर किया जाये। मूल्यांकन किया जाये ऐसा नहीं है कि कि सब 'फ्री

फार आल'। करेंगे लेकिन सलेक्टिव करेंगे और उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढायेंगें लोगों के बिल से इन्फार्मेशन लेंगे। मनोरंजन कर से राजस्व वसूली में 60% वृद्धि हुई मनोरंजन कर से पिछले वर्ष 148 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जब कि इस वर्ष 237 करोड़ रुपये वसूल किये जाने का अनुमान है। अध्यक्ष जी, सरकार इस बात के प्रति अत्यंत सजग है कि कर शुल्कों की दरें आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिये। अचल संपत्ति के क्षेत्र में मंदी को देखते हुए हमारी सरकार ने पिछली नीतियों से भिन्न शहरी क्षेत्रों में सर्कल रेटस स्थिर रखे और कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 31 मार्च 2015 तक स्टैम्प शुल्क वसूली 2769 करोड़ रुपये की हुई थी चालू वित्त वर्ष में 22 मार्च 2016 तक स्टैम्प शुल्क तीन हजार तीन सौ उनसठ करोड़ रुपये पहुंच चुका है जो कि अब तक पिछले वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। इस उपलब्धि को बनाये रखने के लिये विभिन्न नये उपाय प्रस्तावित किये जा रहे हैं ताकि स्टैम्प शुल्क में वृद्धि और की जा सके। दिल्ली के लिये एक अलग स्टैम्प एक्ट तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रावधानों को सरल करना, निरंकुश अधिकारों में कमी लाना और साथ ही राजस्व में वृद्धि करना है। एक नई पहल shares and debentures जारी करने वाली कंपनियों के लिये स्टैम्प शुल्क का आन लाईन भुगतान करने के रूप में की जा रही है। अधिक से अधिक लेन देन को पंजीकृत और स्टैम्प शुल्क के दायरे में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि नई नये संसाधनों, संस्थानों के लिये पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंजीकृत दस्तावेजों के लिये जल्द ही आन

लाईन सर्च सुविधा शुरू करने के लिये तैयारी कर रही है। 1985 के बाद से सभी जितनी भी धरोहर हैं उनको स्कैन करके डिजिटलाइज करेंगे और आम लोगों को आसानी से इसको सर्च के लिये उपलब्ध करायेंगे ताकि कहीं भी कोई सेल परचेज हो, आराम से आदमी आन लाईन उसका डेटा बेस में देख सके। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे कुछ बजट प्रस्ताव थे जिसमें मैंने टैक्स की चर्चा की और मैं फिर से खुशी के साथ कह रहा हूं कि लगातार दूसरा जीरो टैक्स बजट हम लोग प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं यहां पर। मैंने कई मुद्दों पर चर्चा की दिल्ली के लागों की कई जरूरतों पर चर्चा की आखिर में मैं आदरणीय महात्मा गांधी के प्रिय बापू एक कोटैशन से, उनके एक वाक्य से अपनी बात खत्म करूंगा। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था उनका एक स्टेटमेंट और इस पूरे मेरे प्रयासों को एक वित्त मंत्री के रूप में तमाम जितने प्रयास हमने, हमारी टीम ने पिछले दिनों में किये उनको समराइज करते हुए मैं उसको महात्मा गांधी जी के इस वक्तव्य से कैप करना चाहता हूं। ''should love to satisfy all if I personally can but in trying to satisfy all, may be able to satisfy none. I may be able to satisfy none. I have, therefore, arrived at the conclusion that the best course is that satisfy one's own consensus and leave the world to fall its own judgement.'' मुझे सबको संतुष्ट करना अच्छा लगता है बशर्ते ऐसा कर सकना मेरे लिये संभव होता परंतु सभी को संतुष्ट करने के प्रयास में शायद मैं किसी को भी संतुष्ट ना कर पाऊं। इसलिये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे अपनी अंतर्रात्मा को अपने जमीर को अपनी नीयत को संतुष्ट करना चाहिये और दुनिया को अपना निर्णय स्वयं करने के लिये छोड़ देना चाहिये। ये मेरे बजट का concluding remarks है।

ये किसी शायर ने किसी को... आम आमदी है आम आदमी की भाषा में बात रखते हैं। किसी शायर ने इसको बड़े अंदाज में, बड़े बेबाक अंदाज में कहा है कि

मुसल्ला रखते हैं साहबो जाम रखते हैं।
मतलब फकीर हैं सबके लिये इंतजाम रखते हैं।

तो मैं उम्मीद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अंत में एक पिछले बजट में भी मैंने यह बात कही थी कि दिल्ली की इस ऐतिहासिक विधानसभा से निकली हुई सरकार जिस शख्स के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके अदम्य साहस और उसकी सूझबूझ भरे नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं अपनी आखिरी बात उस व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी और ये सदन समर्थन दे सकता है उसके साहस को। पिछले एक साल योजनाओं का रहा, ईमानदारी से काम करने का रहा, संघर्ष का रहा लेकिन साहस दिखाने का भी रहा और उसकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस सदन की तरफ से :

''मैं कतरा होकर भी मैं कतरा होकर भी तूफानों से जंग लेता हूं।

मेरा बचना समंदर की जिम्मेदारी है,
दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी,
दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत मेरी,
ये चिराग कई आंधियों पे भारी है।''

मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के साथ अपने मुख्यमंत्री जी के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। शुक्रिया।

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : भई ओमप्रकाश जी और विजेन्द्र गुप्ता जी खड़े हुए, नहीं हुए लेकिन हमारे जगदीश प्रधान जी खड़े हो गये थे। एक बार तालियां हो जायें। चलिये, माननीय उपमुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि 2016-17 का बजट हाऊस में पेश करें।

उपमुख्य मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I Present the annual budget for the financial year 2016-17 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप-मुख्यमंत्री वर्ष 2016-17 की demand for grants पेश करेंगे।

उप मुख्य मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I Present the demands for grants for the financial year 2016-17.

पूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण व पारण

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उपमुख्यमंत्री 2015-16 के लिए Supplementary demands पेश करेंगे।

उप मुख्य मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I Present second and final batch of Supplementary Demands for the financial year 2015-16 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नं. 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें रेवेन्यू में 6 करोड़ 98 लाख 47 हजार रुपये सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 2 पास हुई।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 3 Administration of Justice जिसमें रेवेन्यू में 278 करोड़ 38 लाख 75 हजार रुपये हैं। सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 3 पास हुई।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 4 फाइनेंस जिसमें रेवेन्यू में एक लाख और कैपिटल में 30 लाख रुपये हैं। कुल राशि 31 लाख रुपये सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 4 पास हुई।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 5 होम। जिसमें रेवेन्यू में दो लाख रुपये हैं। सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 5 पास हुई।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 6 ऐजूकेशन। जिसमें रेवेन्यू में अठारह लाख रुपये हैं। सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 6 पास हुई।

डिमांड नं. 7 मेडिकल एंड पब्लिक हैल्थ। जिसमें रेवेन्यू में 26 लाख रुपये और कैपिटल में 2 लाख रुपये हैं। कुल राशि 28 लाख रुपये सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें

जो इसके विरोध में है, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 7 पास हुई।

डिमांड नं. 8 सोशल वेलफेयर। जिसमें रेवेन्यू में 134 करोड़ 53 लाख और कैपिटल में 197 करोड़ 57 लाख 37 हजार रुपये कुल राशि 332 करोड़ 10 लाख 37 हजार रुपये सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 8 पास हुई।

डिमांड नं. 9 इन्डस्ट्रीज। जिसमें रेवेन्यू में 2 लाख रुपये सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 9 पास हुई।

सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 10 (डेवलेपमेंट)। जिसमें रेवेन्यू में 10 लाख रुपये हैं। सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 10 पास हुई।

डिमांड नं. 11 (अरबन डेवलेपमेंट एंड पब्लिक वर्कस)। जिसमें रेवेन्यू में 61 लाख रुपये और कैपिटल में 798 करोड़ 85 लाख रुपये हैं। कुल राशि 799 करोड़ 46 लाख सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
सप्लीमेंट्री डिमांड नं. 11 पास हुई।

हाऊस में कुल मिलाकर रेवेन्यू में 421 करोड़ 10 लाख 22 हजार रुपये एवं कैपिटल में 996 करोड़ 74 लाख 37 हजार रुपये कुल राशि 1417 करोड़ 84 लाख 59 हजार की सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डस की मंजूरी दी है। Appropriation Bill No. 1 बिल 2016 बिल नं. 1 of 2016 । अब माननीय उपमुख्य मंत्री Appropriation No. 1 Bill No. 1 of 2016 House introduce करने की परमिशन मांगेंगे।

उपमुख्य मंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introuduce Appropiration No. 1 Bill No.1 to the 2016 House.

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के समाने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
प्रस्ताव पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री बिल को सदन में introduce करेंगे।

विनियोग विधेयक सं. 1 (वर्ष 2016)

उप मुख्यमंत्री : Hon'ble Speaker Sir, I introduce Appropriation No. 1 Bill 2016 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब बिल पर clause wise विचार होगा। प्रश्न है कि खंड दो, खंड तीन Schedule Bill का अंग बने :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड दो, खंड तीन Schedule Bill का अंग बन गये। प्रश्न है कि खंड एक preamble और title bill का अंग बने :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

खंड एक preamble और title bill का अंग बन गये। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation Bill No. 1 Bill 2016 को पास किया जाये।

उप मुख्यमंत्री : Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation Bill No. 1 Bill 2016.

अध्यक्ष महोदय : उपमुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें
जो इसके विरोध में है, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

Appropriation No. 1 Bill 2016 पास हुआ।

समय पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्री गोपाल राय जी माननीय परिवहन मंत्री कार्य सूची में दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

परिवहन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दर्शाये गये अपने विभाग से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं :

1. विषम/सम योजना के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 3(218)/एमआरटीएसा/परि.2015/302 दिनांक 28.12.2015 (अंग्रेजी/हिन्दी प्रति)।*[1]

2. मालवाहनों के चलाने एवं निष्प्रयोजन पार्किंग संबंधी अधिसूचना संख्या एफ19(96)/परि.सचि./2010/16 दिनांक 05.02.16 (अंग्रेजी/हिन्दी प्रति)।*[2]

3. दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी/हिन्दी प्रति)।*[3]

---

*1-3 पुस्तकालय में संदर्भ सं. 21, 179 एवं R15530-31 पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सतेन्द्र जैन माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली विद्युत विनयामक आयोग वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट की अंग्रेजी, हिंदी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्युत विनयामक आयोग की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट की अंग्रेजी व हिंदी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।*4

अध्यक्ष महोदय : अब सदन की कार्यवाही आधा घंटा तीस मिनट के लिये स्थगित की जाती है, पुनः तीस मिनट बाद चाय ब्रेक के बाद हम मिलेंगे। धन्यवाद।

सदन अपराह्न 4-45 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

नियम - 116 के अंतर्गत प्रस्ताव

श्री निति त्यागी : That this House postpone the discussion on Motion of Thanks to tomorrow i.e. 29th March, 2016 so that the House could take up immediately a discussion on a very important matter involving security and self respect of the nation vis-a-vis terror attack on Pathankot Airbase and express its sentiments appropriately.

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी, आप अपनी चेयर पर आ जाइये।

श्री नितिन त्यागी : भारत माता की जय। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। न हम उसको वेवकूफ बनने देंगे। हम भी उसी जनता का हिस्सा हैं।

*4 पुस्तकालय में संदर्भ सं. 21, 179 एवं R15530-31 पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी।

श्री नितिन त्यागी : सर एक मिनट। मैं बात कहना चाहता हूं। हम बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में।

श्री नितिन त्यागी : मैं संक्षेप में खत्म करना चाहता हूं। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिये मैं आपके लिये motion forward कर रहा हूं। आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिये। That this House postpone the discussion on Motion of Thanks to tomorrow i.e. 29th March, 2016 so that the House could take up immediately a discussion on a very important matter involving security and self respect of the nation deserving terror attack on Pathankot Airbase and express its sentiments appropriately. सर यह टीम वापिस जानी चाहिए। यह पाकिस्तान वापिस जानी चाहिये। **...व्यवधान...**

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी। मोदी जी, शर्म करो।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, आप अपनी चेयर पर जाओ। आपकी चेयर यही है क्या? आप अपनी चेयर पर बैठें।...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : इसको डाउन करें प्लीज। शर्माजी, सोमनाथ जी प्लीज।...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यह बैनर बन्द करें। ये बैनर बन्द करिये प्लीज। यह नारे बन्द करिये प्लीज। यह बन्द करिये। देखिये सदन में बैनर लेकर आना...। सोमनाथ जी यह बैनर बन्द करिये।

वाजपेयी जी बैनर कलोज करिये। एक तो अपनी कुर्सी पर जाइये प्लीज। यही है आपकी एलाटमेन्ट।

श्री नितिन त्यागी : आईएसआई वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बैनर बन्द करिये। मेरी यह प्रार्थना है। सोमनाथ जी एक बार बैनर बन्द करिये। बन्द करिये यह प्लीज। मैंने सुन लिया। बन्द करिये।...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप बैनर को बन्द करिये। कपिल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने न एक्सेप्ट किया, न रिजेक्ट किया। मंत्री जी खुद कुछ बोलने के लिये खड़े हुए हैं बोल लेने दीजिये दो मिनट।...व्यवधान...इनको एक बार सुन लूं उसके बाद निर्णय देता हूं। सोमनाथ जी बैठिये। यह बैनर को फोल्ड कर लीजिये। मेरी प्रार्थना है। कमांडो जी बैठिये।

पर्यटल एवं जल मंत्री (श्री कपिल मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल शुरूआत में इतना कहना चाहता हूं कि आईएसआई के नागों को भी मोदी जी दूध पिलाते हैं आई एस आई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी, और मेहमानों को बिरयानी और मटन खिलाते हैं मोदी। आईएसआई पाकिस्तान का ज्वाइंट इन्वेस्टीगेशन टीम पठानकोट के अटैक की जांच करने के लिये हिन्दुस्तान बुलाया है उसमें आईएसआई का लेफिटनेंट कर्नल तनवीर अहमद आया है उसमें पाकिस्तान की सेना के आफिसर आये हैं। कौन है आईएसआई। आईएसआई जो पिछले 35 सालों से हिन्दुस्तान में, काश्मीर में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में,

तमिलनाडु में, गुवाहाटी में जो बम ब्लास्ट कराके जिन्होंने हिन्दुस्तानियों को मारा है, वो आईएसआई है। शेम शेम। वो पाकिस्तान की सेना के लोग आये हैं जिन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। इन आतंकवादियों को हथियार दिये और 35 साल से पूरी दुनिया के सामने हिन्दुस्तान कह रहा है कि यह state sponsored terrorism है। पाकिस्तान की सरकार इन आतंकवादियों को भेजती है। लेकिन आज जब नरेन्द्र मोदी जी ने आईएसआई और पाकिस्तान के सेना के डेलीगेशन को बुला लिया पठानकोट के हमले की जांच के लिये तो मैं मोदी जी यह सवाल पूछन चाहता हूं कि क्या आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है। क्या पाकिस्तान की सेना को क्लीन चिट दी है। अगर क्लीन चिट दी है तो कौन सी मजबूरी है क्लीन चिट को देने की, कौन सी डील हुई है इस क्लीन चिट को देने की। अगर क्लीन चिट नहीं दी तो जो हमें मारेगा, वही जांच करेगा। वही आकर बतायेगा कि कैसे हमले हुए। यह आईएसआई वाले पठानकोट में क्या देखने आ रहे हैं? यह देखने आ रहे हैं कि अगली बार और ज्यादा लोगों को कैसे मारा जाये। इसकी जांच करने के लिये क्या वो आ रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमेशा से पाकिस्तान कहता रहा कि आतंकवाद उनकी तरफ से नहीं फैलाया जाता और हिन्दुस्तान कहता था कि यह State sponsored terrorism हैं इसमें आईएसआई का हाथ है। इसमें सेना का हाथ है। पाकिस्तान यह चाहता था कि आतंकवाद के खिलाफ यह पूरी डिबेट स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में बंट जाये और पाकिस्तानी ही मारे और पाकिस्तान ही जांच करे। आज पाकिस्तान के उसी जाल के आगे फंस चुके हैं नरेन्द्र मोदी जी। 35 साल की हिन्दुस्तान की लड़ाई को जिस प्रकार से कमजोर किया गया है मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं बहुत दुख के साथ, और दर्द

के साथ और गुस्से के साथ कहना चाहता हूं कि जो आदमी आईएसआई को हिन्दुस्तान में लेकर आयेगा वो चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो, हम उसको जयचंद कहेंगे, जयचन्द कहेंगे, जयचन्द कहेंगे। अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी का खून नहीं खौला।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी।

पर्यटन एवं जल मंत्री : उनकी आंखों में गुस्सा नहीं आया। उनको रोना नहीं आया किसको बुलाना चाह रहे हैं हिन्दुस्तान के अन्दर? किसको बुलाना चाह रहे हैं? जिसने भारत माता के आंचल पर खून के दाग बिखेरे हैं उनको आज भारत सरकार के दफ्तरों में मेहमान बना कर रखा जा रहा है। सरकारी मेहमान बना कर रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय एक बात बताइये। हाफिज सईद कहां हैं, पाकिस्तान में है। सलाउदीन कहां है पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम कहां है पाकिस्तान में है। अगर नरेन्द्र मोदी तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है नवाज शरीफ से तो भारत की सेना जाये पाकिस्तान।

अध्यक्ष महोदय : कपिल जी, अब इसको बंद करिये।

पर्यटन एवं जल मंत्री : और इन आतंकवादियों को घसीटते हुए जिन्दा या मुर्दा हिन्दुस्तान में लेकर आये। तब तो हम मानेंगे कि तुमने हिन्दुस्तान की मां के कर्ज को चुकाने के बारे में सोचा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हम हमदर्दी खोज रहे हैं आईएसआई वाले गैरों में मोदी जी ने पगड़ी रख दी नवाज शरीफ के पैरों में।

अध्यक्ष महोदय : यह बैनर फोल्ड करिये।

पर्यटन एवं जल मंत्री (कपिल मिश्रा) : हम आईएसआई को पठानकोट में नहीं जाने देंगे। आईएसआई Go back, go back, go back, आईएसआई Go back, go back, go back, पाकिस्तान go back, go back, go back, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।

अध्यक्ष महोदय : हाऊस 15 मिनट के लिये Adjourned किया जाता है।

सदन अपराह्न 5.23 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए*

(सत्ता पक्ष द्वारा सदन में सामूहिक नारेबाजी।)

(श्री नितिन त्यागी वैल आकर नारे लगाने लगे।)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी ऐसे नहीं चलेगा, अपनी सीट पर चलिए। ...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा वैल में आकर सामूहिक नारेबाजी।)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी आप बाहर जाए। नितिन त्यागी बाहर जाए। जगदीप जी, नितिन जी बाहर जाएं

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी को आज के लिए बाहर किया जाता है।

(श्री नितिन त्यागी को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर किया गया)

...व्यवधान...

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा वैल में आकर सामूहिक नारेबाजी।)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं समय कम है, अनेक विषयों पर चर्चा होनी है

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : मैं बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं। मैं खड़ा हूं समझ लीजिए इस बात को ...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदय : सदन की कार्यवाही 29 मार्च 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 29 मार्च 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

विषय-सूची

सत्र-3 भाग (1) सोमवार, 28 मार्च, 2016/08 चैत्र, 1938 (शक) अंक 28

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	शोक संवदेना	3-4
3.	बजट प्रस्तुतीकरण (2016-17)	4-75
4.	पूरक मांगों का प्रस्तुतीकरण विचार एवं पारण (2015-16)	75-79
5.	विनियोग विधेयक सं. 1 (2016) का पुर: स्थापन विचार एवं पारण	80-81
6.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	81-82
7.	प्रस्ताव (नियम-116)	82-88